

एमडीआर-66 कार्ट रोड टूटी कंडी से संजौली वाया छोटा शिमला, एमडीआर-67 विकट्री टनल से संजौली वाया लक्कड़ बाजार तक, के चौड़ीकरण/सुधार तथा तिब्बती स्कूल के पास पैदल पथ के निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन, जिला शिमला हि० प्र० .

हिमाचल प्रदेश भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक प्रभाव आकलन और सहमति) नियम, 2015

मसौदा रिपोर्ट

द्वारा
प्लान फाउंडेशन



प्रस्तुत
सामाजिक समाघात अध्ययन इकाई, हि० प्र०

अनुक्रमणिका

तालिकाओं की सूची	III
आकृतियों की सूची.....	IV
शब्दावली	VI
कार्यकारी सारांश	X
1. विस्तृत परियोजना विवरण.....	1
1.1 परियोजना पृष्ठभूमि	1
1.1.1 अंतर-राज्यीय/अंतर्राष्ट्रीय पहलू.....	2
1.1.2 डेवलपर्स पृष्ठभूमि.....	3
1.2 परियोजना का औचित्य और सार्वजनिक उद्देश्य	3
1.3 परियोजना विवरण	5
1.3.1 परियोजना का आकार.....	6
1.3.2 स्थान	6
1.3.3 क्षमता और उत्पादन.....	7
1.3.4 परियोजना लागत और जोखिम.....	8
1.4 विकल्पों की जांच.....	8
1.5 परियोजना निर्माण के चरण.....	8
1.6 मुख्य डिजाइन विशेषताएँ, आकार और सुविधाओं के प्रकार	8
1.7 कार्यबल की आवश्यकताएँ	8
1.8 पर्यावरण प्रभाव आकलन और तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट का विवरण.....	9
1.9 लागू कानून और नीतियाँ	9
1.9.1 सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन की तैयारी	9
1.9.2 भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया.....	10
1.9.3 भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013.....	11
1.9.4 हिमाचल प्रदेश आरटीएफसीटीएलएआरआर नियम 2015.....	13
2. सामाजिक प्रभाव आकलन की टीम संरचना, दृष्टिकोण, कार्यप्रणाली और अनुसूची.....	16
2.1 टीम का विवरण	16
2.2 कार्यप्रणाली और प्रयुक्त उपकरणों का विवरण और औचित्य	16
2.2.1 लक्ष्य.....	18
2.2.2 उद्देश्य.....	18
2.2.3 दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली	19
2.2.4 कार्यप्रणाली का औचित्य.....	20
2.3 सामाजिक प्रभाव आकलन के लिए जानकारी एकत्र करने के उपकरण	21
2.4 नमूनाकरण पद्धति.....	22
2.5 प्रयुक्त सूचना और डेटा स्रोतों का अवलोकन	23
3. भूमि मूल्यांकन	25
3.1 भूमि सूची और प्राथमिक स्रोतों से जानकारी	25
3.2 परियोजना के प्रभाव में आने वाला संपूर्ण क्षेत्र	26
3.3 परियोजना के लिए कुल भूमि की आवश्यकता.....	27

3.4	क्षेत्र के आस-पास किसी सार्वजनिक, अप्रयुक्त भूमि का वर्तमान उपयोग.....	27
3.5	परियोजना के लिए आवश्यक प्रत्येक भूखंड के लिए पहले से खरीदी गई, हस्तांतरित, पट्टे पर दी गई/अधिग्रहित भूमि और इच्छित उपयोग.....	28
3.6	परियोजना के लिए अधिग्रहित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि की मात्रा और स्थान	29
3.7	भूमि की प्रकृति, वर्तमान उपयोग और वर्गीकरण	30
3.8	जोतों का आकार, स्वामित्व पैटर्न.....	30
3.9	भूमि वितरण और अधिग्रहित किए जा रहे आवासीय घरों की संख्या	30
3.10	भूमि की कीमतें तथा स्वामित्व और हस्तांतरण में हाल ही में हुए परिवर्तन	31
4.	प्रभावित परिवारों और संपत्तियों का आकलन और गणना	33
4.1	सीधे प्रभावित व्यक्ति	33
4.1.1.	किराएदार/कब्जाधारी.....	33
4.1.2.	साझा संपत्ति संसाधनों (सीपीआर) पर निर्भरता.....	34
4.1.3.	आजीविका के लिए भूमि पर निर्भरता.....	34
5.	सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक प्रोफाइल	35
5.1	परियोजना क्षेत्र में परियोजना से प्रभावित लोगों की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल.....	35
5.2	आय और गरीबी का स्तर.....	36
5.3	परियोजना प्रभावित परिवारों की साक्षरता स्थिति.....	37
5.4	कमजोर समूह.....	38
5.5	रिश्तेदारी पैटर्न.....	38
5.6	प्रशासनिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और नागरिक समाज संगठन.....	39
5.7	क्षेत्रीय गतिशीलता और ऐतिहासिक परिवर्तन प्रक्रियाएँ.....	40
5.8	रहने के माहौल की गुणवत्ता	42
6.	सामाजिक प्रभाव	43
6.1	प्रभावों की पहचान करने के लिए रूपरेखा और दृष्टिकोण	43
6.2	6.2 परियोजना के विभिन्न चरणों में प्रभावों का विवरण.....	44
6.3	परियोजना प्रभावित व्यक्तियों द्वारा अनुभव किए गए प्रभाव	46
6.4	एमडीआर परियोजना के बारे में जागरूकता	47
6.5	परियोजना के लिए सहमति	47
6.6	मुआवजे की प्राथमिकताएँ	47
7.	लागत और लाभ का विश्लेषण तथा अधिग्रहण पर सिफारिशें	48
7.1	सार्वजनिक उद्देश्य का मूल्यांकन.....	48
7.2	कम विस्थापन विकल्प और न्यूनतम भूमि आवश्यकता	50
7.3	सामाजिक प्रभावों की प्रकृति और तीव्रता	50
7.4	सुझाए गए शमन उपायों की व्यवहार्यता	50
7.4.1.	अंतिम अनुशंसा.....	52
8.	सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना	55
8.1	शमन का दृष्टिकोण	55
8.2	प्रभावों से बचने, उन्हें कम करने और क्षतिपूर्ति करने के उपाय.....	56
8.3	अधिनियम 2013 के अनुसार पुनर्वास और पुनर्वास में शामिल उपाय और मुआवजा	56
8.3.1.	एसआईएमपी कार्यान्वयन के लिए परिचय.....	57

तालिकाओं की सूची

तालिका 1-1 शिमला, हिमाचल प्रदेश में एमडीआर 66 और एमडीआर-67 की परियोजना विवरण	5
तालिका 2-1 सामाजिक प्रभाव आँकलन टीम संरचना और विशेषज्ञता.....	17
तालिका 2-2 सामाजिक प्रभाव आँकलन के लिए क्षेत्र सर्वेक्षकों की सूची.....	17
तालिका 3-1 शिमला में परियोजना एमडी आर66और 67 के लिए अधिग्रहीत की जाने वाली कुल भूमि और खसरा संख्या.....	25
तालिका 3-2 शिमला में परियोजना एमडी आर66और 67 के लिए अधिग्रहीत की जाने वाली कुल भूमि और खसरा संख्या.....	26
तालिका 3-3 शिमला, हिमाचल प्रदेश में परियोजना एमडीआर 66 और 67 के तहत भूमि अधिग्रहण से प्रभावित आवासीय और वाणिज्यिक संरचनाओं का अवलोकन	32
तालिका 5-1 परियोजना से सीधे प्रभावित लोगों की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल	35
तालिका 6-1 परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों में सामाजिक प्रभावों का विवरण.....	46
तालिका 7-1 प्रभावों की प्रकृति और तीव्रता.....	51
तालिका 8-1 पहचाने गए प्रभाव और तदनुरूप शमन उपाय.....	57
तालिका 8-2 पात्रता मैट्रिक्स	58

आकृतियों की सूची

आकृति 2-1 एमडीआर 66 और 67 के चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण में सामाजिक प्रभाव आँकलन आयोजित करने के लिए प्रवाह चार्ट.....	20
आकृति 4-1 शिमला, हिमाचल प्रदेश में परियोजना एमडीआर 66 और 67 में परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की स्वामित्व स्थिति.....	33
आकृति 5-1 प्रभावित परिवारों का आय वितरण.....	36
आकृति 5-2 शिमला, हिमाचल प्रदेश में परियोजना प्रभावित परिवारों के बीच शिक्षा की स्थिति (%).....	37

शब्दावली

- अधिनियम का अर्थ है: भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30)।
- प्रभावित क्षेत्र का अर्थ है ऐसा क्षेत्र जिसे भूमि अधिग्रहण के प्रयोजनों के लिए उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।
- प्रभावित परिवार में शामिल हैं:
 - I. ऐसा परिवार जिसकी भूमि या अन्य अचल संपत्ति अधिग्रहित की गई हो।
 - II. ऐसा परिवार जिसके पास कोई भूमि नहीं है, लेकिन ऐसे परिवार के सदस्य कृषि मजदूर, काश्तकार, जिसमें किसी भी प्रकार की काश्तकारी या उपभोग अधिकार शामिल हैं, बटाईदार या कारीगर हो सकते हैं या जो भूमि अधिग्रहण से तीन साल पहले प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे हों, जिनकी आजीविका का प्राथमिक स्रोत भूमि अधिग्रहण से प्रभावित हो।
 - III. अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य परंपरागत वनवासी जिन्होंने भूमि अधिग्रहण के कारण अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त अपने किसी भी वन अधिकार को खो दिया है।
 - IV. ऐसा परिवार जिसकी भूमि अधिग्रहण से तीन वर्ष पूर्व तक आजीविका का प्राथमिक स्रोत वनों या जल निकायों पर निर्भर था और जिसमें वनोपज संग्रहकर्ता, शिकारी, मछुआरे और नाविक शामिल हैं और ऐसी आजीविका भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित हुई है।
 - V. परिवार का कोई सदस्य जिसे राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा उसकी किसी योजना के अंतर्गत भूमि आवंटित की गई है और ऐसी भूमि अधिग्रहण के अधीन है।
 - VI. ऐसा परिवार जो भूमि अधिग्रहण से पिछले तीन वर्ष या उससे अधिक समय से शहरी क्षेत्रों में किसी भूमि पर रह रहा हो या जिसकी भूमि अधिग्रहण से पहले

तीन वर्षों तक आजीविका का प्राथमिक स्रोत ऐसी भूमि के अधिग्रहण से प्रभावित हुआ हो।

- कृषि भूमि का अर्थ है वह भूमि जिसका उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है:
 - I. कृषि या बागवानी।
 - II. डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, मछली पालन, रेशम उत्पादन, बीज खेती, पशुधन या नर्सरी का प्रजनन, औषधीय जड़ी-बूटियाँ उगाना।
 - III. फसल, पेड़, घास या बगीचे के उत्पाद उगाना; और
 - IV. मवेशियों के चरने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भूमि।
- गरीबी रेखा से नीचे या बीपीएल परिवार का तात्पर्य भारत के योजना आयोग द्वारा समय-समय पर परिभाषित गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश की बीपीएल सूची में शामिल परिवारों से है।
- केंद्र सरकार का तात्पर्य भारत सरकार से है।
- मुआवजा अधिनियम 2013 के विभिन्न प्रावधानों के तहत परियोजना के लिए अधिग्रहित निजी संपत्ति, संरचनाओं और अन्य परिसंपत्तियों के लिए मुआवजे के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि को संदर्भित करता है, जिसमें पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिकार शामिल हैं।
- परिवार में एक व्यक्ति, उसका पति या पत्नी, नाबालिग बच्चे, नाबालिग भाई और उस पर निर्भर नाबालिग बहनें शामिल हैं: बशर्ते कि विधवाओं, तलाकशुदा और परिवारों द्वारा परित्यक्त महिलाओं को अलग परिवार माना जाएगा।
- भूमि में भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ, तथा धरती से जुड़ी हुई वस्तुएँ या धरती से जुड़ी हुई किसी भी वस्तु से स्थायी रूप से जुड़ी हुई वस्तुएँ शामिल हैं।

- भूमि अधिग्रहण का अर्थ है भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत भूमि का अधिग्रहण।
- भूमिहीन का अर्थ है ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जो: किसी राज्य कानून के अंतर्गत इस प्रकार माना या निर्दिष्ट किया जा सकता है; या खंड (i) के अंतर्गत निर्दिष्ट न किए गए भूमिहीन के मामले में, जैसा कि उपयुक्त सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है;
- भूमि स्वामी में कोई भी व्यक्ति शामिल है-
 - I. जिसका नाम संबंधित प्राधिकारी के अभिलेखों में भूमि या भवन या उसके भाग के स्वामी के रूप में दर्ज है; या
 - II. कोई भी व्यक्ति जिसे अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) या किसी अन्य कानून के अंतर्गत वन अधिकार प्रदान किए गए हैं; या
 - III. जो राज्य के किसी कानून के तहत भूमि पर पट्टा अधिकार प्राप्त करने का हकदार है, जिसमें सौंपी गई भूमि भी शामिल है; या
 - IV. कोई व्यक्ति जिसे न्यायालय या प्राधिकरण के आदेश द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो;
- बाजार मूल्य का अर्थ है अधिनियम 2013 की धारा 26 के अनुसार निर्धारित भूमि का मूल्य।
- अधिसूचना का अर्थ है भारत के राजपत्र में या, जैसा भी मामला हो, किसी राज्य के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना और "अधिसूचित" शब्द का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा।
- सार्वजनिक उद्देश्य का अर्थ है अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा (1) के तहत निर्दिष्ट गतिविधियाँ।
- पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) का अर्थ है आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 के अनुसार पुनर्वास और पुनर्स्थापन करना।

- अनुसूचित क्षेत्रों का अर्थ है पंचायतों (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का 40) के प्रावधानों की धारा 2 में परिभाषित अनुसूचित क्षेत्र।
- सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन का अर्थ है अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के तहत किया गया मूल्यांकन।
- सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना का अर्थ है अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अंतर्गत सामाजिक प्रभाव आकलन प्रक्रिया के भाग के रूप में तैयार की गई योजना।
- राज्य सरकार या “सरकार” का अर्थ है हिमाचल प्रदेश सरकार
- किरायेदार वे व्यक्ति हैं जिनके पास भूमि अधिग्रहण से तीन वर्ष पूर्व स्पष्ट संपत्ति स्वामित्व वाले संपत्ति स्वामी के साथ निवास, व्यवसाय या अन्य उद्देश्यों के लिए किसी संरचना या भूमि पर कब्जा करने के लिए वास्तविक किरायेदारी समझौते हैं।
- कमजोर समूहों में विकलांग, विधवाएं, महिला मुखिया वाले परिवार, साठ वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य समूह शामिल हैं।
- महिला मुखिया वाले परिवार का अर्थ है एक ऐसा परिवार जिसका मुखिया महिला है और जिसमें कोई पुरुष कमाने वाला सदस्य नहीं है। यह महिला विधवा, अलग हुई या परित्यक्त महिला हो सकती है।

कार्यकारी सारांश

परियोजना पृष्ठभूमि

हिमाचल प्रदेश के शिमला में प्रमुख जिला सड़कों (एमडीआर) 66 और 67 का चौड़ीकरण और सुधार, एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसका उद्देश्य बढ़ती यातायात भीड़ को संबोधित करना और परिवहन दक्षता को बढ़ाना है। ये सड़कें शहर के बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक हैं, जो निवासियों, पर्यटकों और व्यवसायों के लिए प्रमुख मार्गों के रूप में काम करती हैं। शिमला के तेजी से विकास ने इसके सड़क नेटवर्क पर मांग में वृद्धि की है, जिसे मूल रूप से कम आबादी और कम वाहन यातायात के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस परियोजना में टुटी कंडी विभाजन से छोटा शिमला होते हुए संजौली ढली बाईपास तक और विक्ट्री टनल से लक्कड़ बाजार होते हुए संजौली ढली तक सड़क खंडों को चौड़ा करना, साथ ही छोटा शिमला से कसुम्पती सड़क के साथ तिब्बती स्कूल के पास पैदल यात्री पथ का निर्माण करना शामिल है।

अंतर-राज्यीय/अंतर्राष्ट्रीय पहलू

एमडीआर 66 और 67 परियोजनाएँ राज्य के अधिकार क्षेत्र में हैं, जिनका प्रबंधन पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है, जिसका कोई अंतरराज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव नहीं है। पड़ोसी राज्यों या देशों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरती गई हैं।

डेवलपर की पृष्ठभूमि

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (एचपीपीडब्ल्यूडी) इस परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार एजेंसी है। एचपीपीडब्ल्यूडी को बुनियादी ढांचे के विकास में व्यापक अनुभव है, खासकर चुनौतीपूर्ण इलाकों में। उनका काम कनेक्टिविटी को बढ़ाता है और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, खासकर पर्यटन और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में।

परियोजना का औचित्य

शिमला के सड़क नेटवर्क पर बढ़ती आबादी और वाहन यातायात के कारण काफी दबाव है, जिससे लगातार भीड़भाड़ और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ पैदा होती हैं। सड़क सुधार पहल का लक्ष्य इन मुद्दों को कम करना है:

- यातायात भीड़भाड़ को कम करना: यातायात प्रवाह को आसान बनाने के लिए सड़कों को चौड़ा करना, खासकर पीक ऑवर्स और पर्यटन सीजन के दौरान।
- सड़क सुरक्षा में सुधार: दुर्घटनाओं को कम करने और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण।
- कनेक्टिविटी बढ़ाना: शहर के प्रमुख क्षेत्रों के बीच अधिक कुशल आवागमन की सुविधा प्रदान करना और आवश्यक सेवाओं तक पहुँच में सुधार करना।
- सतत शहरी विकास का समर्थन करना: शहर के बढ़ने के साथ शिमला की विकसित होती परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करना।
- आर्थिक और सामाजिक लाभ बढ़ाना: स्थानीय आर्थिक गतिविधियों और पर्यटन को बढ़ाने के लिए परिवहन अवसंरचना में सुधार करना, जिससे निवासियों के जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार हो।

यह परियोजना भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन (RTFCTLARR) अधिनियम, 2013 में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत उचित है, क्योंकि यह सार्वजनिक उद्देश्य के लिए मानदंडों को पूरा करती है। हितधारकों की चिंताओं को दूर करने के लिए राज्य के नियमों के अनुपालन में एक सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) आयोजित किया गया है।

परियोजना विवरण

इस परियोजना में प्रमुख मार्गों के साथ भूमि और भवनों का अधिग्रहण शामिल है, जिसमें टुटी कंडी विभाजन के पास के क्षेत्र संजौली और ढली से छोटा शिमला और विकट्री सुरंग से संजौली ढली तक लक्कड़ बाज़ार जंक्शन के माध्यम से क्षेत्र शामिल हैं। तिब्बती स्कूल के पास कसुम्पती सड़क तक पैदल यात्री पथ का निर्माण सुरक्षा सुधारों का हिस्सा है। एस०आई०ए इन क्षेत्रों को कवर करता है और भूमि अधिग्रहण से संबंधित सामाजिक प्रभावों का व्यापक मूल्यांकन प्रदान करता है।

परियोजना का आकार

इस परियोजना के लिए 12 गांवों में 20,882.53 वर्ग मीटर भूमि का अधिग्रहण करना होगा। इसका मुख्य लक्ष्य शिमला की बढ़ती आबादी और पर्यटन की मांग को पूरा करने के लिए सड़क चौड़ीकरण और बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। यातायात प्रबंधन में इस विकास की महत्वपूर्ण आवश्यकता के कारण कोई व्यवहार्य विकल्प प्रस्तावित नहीं किया गया है।

पर्यावरण और जोखिम संबंधी विचार

मुख्य जोखिमों में जल निकासी और भूकंपीय क्षेत्र IV में निर्माण से संबंधित पर्यावरणीय चिंताएँ शामिल हैं। पहाड़ी क्षेत्र में परियोजना का स्थान अतिरिक्त निर्माण चुनौतियाँ पेश करता है, जिसके लिए शमन रणनीतियों की आवश्यकता होगी।

कनेक्टिविटी और भौगोलिक विचार

शिमला की अनूठी भौगोलिक स्थिति, जो कई पहाड़ियों पर फैली हुई है, निर्माण को जटिल बनाती है। यह क्षेत्र जुबबड़हट्टी हवाई अड्डे और कालका-शिमला रेलवे सहित क्षेत्रीय परिवहन केंद्रों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जिससे संसाधनों और कर्मियों की पहुँच आसान हो जाती है।

कानूनी ढांचा और भूमि अधिग्रहण

भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार (RTFCTLARR) अधिनियम, 2013 द्वारा शासित है। सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) और सार्वजनिक परामर्श पूरे प्रोजेक्ट में सामुदायिक भागीदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं।

अध्ययन के उद्देश्य

इस एस०आई०ए का प्राथमिक उद्देश्य परियोजना के गलियारे के साथ समुदायों, घरों और व्यवसायों पर परियोजना के संभावित सामाजिक प्रभावों का आकलन करना है। रिपोर्ट प्रतिकूल प्रभावों को कम करने और प्रभावित आबादी को उचित मुआवजा और पुनर्वास प्रदान करने के लिए आवश्यक कदमों की रूपरेखा भी प्रस्तुत करती है।

कार्यप्रणाली

एस०आई०ए को बहु-विधि दृष्टिकोण का उपयोग करके किया गया था, जिसमें घरेलू सर्वेक्षण, हितधारक परामर्श और साइट का दौरा शामिल था। एस०आई०ए टीम ने प्रासंगिक डेटा एकत्र करने और प्रभावों का आकलन करने के लिए लगन से काम किया। तालिका 2-2 में सर्वेक्षणकर्ताओं की सूची दी गई है

भूमि मूल्यांकन

शिमला में प्रस्तावित सड़क विकास परियोजना के लिए 12 गांवों और 378 खसरा नंबरों में 20,882.53 वर्ग मीटर (2.0883 हेक्टेयर) भूमि का अधिग्रहण करना आवश्यक है। भूमि का उपयोग सड़क चौड़ीकरण, पैदल पथ के निर्माण और अन्य आवश्यक बुनियादी ढाँचे में सुधार के लिए किया जाएगा।

भूमि उपयोग और स्वामित्व

भूमि में रास्ते, बरामदे, सड़कें, सीढ़ियाँ और वन क्षेत्र, साथ ही आवासीय और वाणिज्यिक संरचनाएँ शामिल हैं।

स्वामित्व पैटर्न से पता चलता है कि अधिकांश भूमि पैतृक स्वामित्व वाली है, जिसमें कुछ किरायेदार का आवासीय या वाणिज्यिक उपयोग के लिए संपत्ति पर कब्जा है। अधिग्रहण से दोनों समूह प्रभावित होंगे।

भूमि दोहरे उद्देश्यों को पूरा करती है, जिसका उपयोग आवासीय और वाणिज्यिक दोनों गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, जिससे परिवारों और व्यवसायों पर इसके प्रभाव पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

मुआवजा और भूमि मूल्यांकन

भूमि मालिक आधिकारिक सर्किल दरों के बजाय वर्तमान बाजार मूल्यों के आधार पर मुआवजे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि बाद में उनकी संपत्तियों का कम मूल्यांकन किया जाता है। हाल ही में भूमि की बिक्री के दस्तावेज न होने से बाजार मूल्य और सर्किल दरों के बीच विसंगतियां पैदा हुई हैं, जिसके बारे में भूमि मालिकों का मानना है कि यह उनकी भूमि के वास्तविक मूल्य

को नहीं दर्शाता है। संक्षेप में, यह परियोजना आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों के मिश्रण को प्रभावित करेगी, भूमि मालिक आधिकारिक भूमि मूल्यांकन में विसंगतियों के कारण बाजार आधारित मुआवजे की वकालत कर रहे हैं।

प्रभावित परिवारों और संपत्तियों का आकलन और गणना

शिमला में प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण और विकास परियोजना कई परिवारों, किरायेदारों और वाणिज्यिक संपत्ति मालिकों को प्रभावित करेगी। यह खंड सीधे प्रभावित होने वाले लोगों का अवलोकन प्रदान करता है, जिसमें उनकी आजीविका पर भूमि अधिग्रहण का प्रभाव भी शामिल है।

सीधे प्रभावित व्यक्ति किराएदार/कब्जाधारी

शिमला, राज्य का सबसे बड़ा शहर है, जिसमें किराए के घरों का अनुपात बहुत अधिक है, जिसमें 64.7% घर किराए के हैं और 35.3% खुद के हैं। अधिग्रहण से प्रभावित होने वाली कई इमारतों में किराएदार हैं जो इस प्रक्रिया से प्रभावित होंगे।

आजीविका के लिए भूमि पर निर्भरता: बहुत से हितधारक व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अधिग्रहित संपत्तियों पर निर्भर हैं, जो उनकी आजीविका का प्राथमिक स्रोत है।

साझा संपत्ति संसाधन (सीपीआर): अधिग्रहण के लिए निर्धारित भूमि पर कोई सीपीआर की पहचान नहीं की गई।

शिमला का सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक प्रोफाइल

जनसांख्यिकी: अध्ययन ने प्रभावित आबादी की जनसांख्यिकी प्रोफाइल का विश्लेषण किया, जिसमें लिंग, आयु वितरण और घरेलू आकार शामिल हैं।

आर्थिक: आय के स्तर का आकलन किया गया, जिससे पता चला कि आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे रह रहा है। छोटे व्यवसाय, विशेष रूप से प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण स्थलों से संचालित होने वाले व्यवसाय, कई निवासियों के लिए आय का प्राथमिक स्रोत हैं।

शैक्षिक: पुरुष और महिला PAF के बीच शैक्षिक प्राप्ति में असमानता की पहचान की गई, जिसमें महिलाओं में शिक्षा का स्तर अधिक था।

सामाजिक: रिश्तेदारी पैटर्न, सांस्कृतिक प्रथाओं और सामुदायिक गतिशीलता की जांच की गई। अध्ययन ने पैतृक भूमि स्वामित्व के महत्व और घरेलू मामलों में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला।

पर्यावरण: वायु प्रदूषण, जल गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए रहने के पर्यावरण की गुणवत्ता का आकलन किया गया। शहरीकरण और पर्यावरण संरक्षण की चुनौतियों पर चर्चा की गई।

कुल मिलाकर, अध्ययन शिमला में प्रभावित समुदायों की सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियों की व्यापक समझ प्रदान करता है। प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के संभावित प्रभावों को संबोधित करने के लिए प्रभावी शमन रणनीतियों को विकसित करने के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है।

एमडीआर-66 और एमडीआर-67 सड़क परियोजना के सामाजिक प्रभाव नकारात्मक प्रभाव:

इस परियोजना से प्रभावित समुदायों पर महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जिसमें भूमि अधिग्रहण, विस्थापन, आजीविका का नुकसान और दैनिक जीवन में व्यवधान शामिल हैं।

नकारात्मक प्रभाव: इस परियोजना से प्रभावित समुदायों पर महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है, जिसमें भूमि अधिग्रहण, विस्थापन, आजीविका का नुकसान और दैनिक जीवन में व्यवधान शामिल हैं।

सकारात्मक प्रभाव: संभावित सकारात्मक प्रभावों में बेहतर कनेक्टिविटी, आर्थिक विकास और पर्यटन में वृद्धि शामिल है।

सार्वजनिक धारणा: कई प्रभावित व्यक्तियों ने परियोजना के बारे में चिंता व्यक्त की, विशेष रूप से संपत्ति और आजीविका के नुकसान के बारे में।

मुआवजे की प्राथमिकताएँ: प्रभावित व्यक्तियों ने मुख्य रूप से मुआवजे के रूप में भूमि और बाजार दरों पर नकद भुगतान की मांग की।

कुल मिलाकर, परियोजना के सामाजिक प्रभाव जटिल और बहुआयामी हैं। हालांकि इसके संभावित लाभ हैं, लेकिन नकारात्मक परिणामों, खासकर कमजोर समूहों के लिए, पर सावधानीपूर्वक विचार करने और उन्हें कम करने की आवश्यकता है।

एमडीआर-66 और एमडीआर-67 सड़क चौड़ीकरण के लिए लागत और लाभ का विश्लेषण

- सार्वजनिक उद्देश्य: यह परियोजना कई सार्वजनिक उद्देश्यों को पूरा करती है, जिसमें बेहतर बुनियादी ढाँचा, कनेक्टिविटी, आर्थिक विकास, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन शामिल हैं।
- विकल्प: मौजूदा सड़कों के आस-पास की भूमि का अधिग्रहण करने के अलावा कोई व्यवहार्य विकल्प नहीं है।
- सामाजिक प्रभाव: इस परियोजना के महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव होंगे, जिसमें विस्थापन, आजीविका का नुकसान और पर्यावरणीय प्रभाव शामिल हैं।
- शमन उपाय: जबकि कुछ शमन उपाय प्रस्तावित हैं, उनकी प्रभावशीलता पर सवाल उठाए गए हैं, विशेष रूप से मुआवजे और किरायेदार अधिकारों के संबंध में।
- व्यवहार्यता: परियोजना की व्यवहार्यता सार्वजनिक लाभों को सामाजिक लागतों के साथ संतुलित करने और प्रभावित पक्षों के लिए उचित मुआवजा और उपचार सुनिश्चित करने पर निर्भर करती है।

सिफारिश:

- सावधानी से आगे बढ़ें: परियोजना आगे बढ़ सकती है, लेकिन केवल सामाजिक प्रभावों और मजबूत शमन उपायों के कार्यान्वयन पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद।
- मुआवजे को प्राथमिकता दें: प्रभावित व्यक्तियों द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त मुआवजा और पुनर्वास योजनाएँ आवश्यक हैं।
- सार्वजनिक हित में संतुलन: सरकार को बुनियादी ढांचे के विकास में सार्वजनिक हित और प्रभावित लोगों के व्यक्तिगत हितों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करना चाहिए।

- निरंतर निगरानी: यह सुनिश्चित करने के लिए कि शमन उपाय प्रभावी हैं और सार्वजनिक लाभ प्राप्त हो रहे हैं, परियोजना के कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी की जानी चाहिए।

सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एस० आई० एम० पी०)

मुख्य उद्देश्य:

- सड़क चौड़ीकरण परियोजना के नकारात्मक सामाजिक प्रभावों को कम करना।
- प्रभावित हितधारकों के लिए न्यायसंगत परिणाम सुनिश्चित करना।
- प्रभावित समुदायों की सामाजिक-आर्थिक भलाई को संरक्षित करना।

मुख्य हस्तक्षेप:

- विवाद समाधान: हितधारकों के बीच विवादों को संबोधित करना और कानूनी मालिकों को मुआवज़ा सुनिश्चित करना।
- मुआवज़ा: उचित मुआवज़े के लिए सर्किल दरों को अपडेट करना और बढ़ाना।
- पुनर्वास: स्थानांतरित व्यवसायों के लिए स्थान आवंटित करना।
- पर्यावरण शमन: निर्माण के दौरान पर्यावरण क्षरण को रोकने के उपायों को लागू करना।
- पात्रता मैट्रिक्स: कानूनी प्रावधानों के आधार पर मुआवज़े और पुनर्वास के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा विकसित करना।

कुल मिलाकर, एस० आई० एम० पी० का उद्देश्य सतत विकास को बढ़ावा देते हुए और कमज़ोर आबादी की रक्षा करते हुए परियोजना के नकारात्मक सामाजिक प्रभावों को कम करना है।

1. विस्तृत परियोजना विवरण

1.1 परियोजना पृष्ठभूमि

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, जिसे अक्सर "पहाड़ों की रानी" कहा जाता है, न केवल एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, बल्कि एक तेज़ी से उभरता हुआ शहरीकरण का केंद्र भी है। इसकी सुंदरता, औपनिवेशिक वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत हर साल लाखों आगंतुकों को आकर्षित करती है, जिससे पर्यटन शहर के मुख्य आर्थिक कारकों में से एक बन जाता है। वहीं दूसरी ओर शिमला की अनूठी स्थलाकृति - खड़ी पहाड़ियों, संकरी घुमावदार सड़कें और सीमित समतल भूमि, शहर की गतिशीलता और बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पेश करती है।

चूंकि शिमला की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, भारतीय जनगणना (भारतीय जनगणना) के अनुसार 2001 में लगभग 1.44 लाख से बढ़कर 2011 में 1.69 लाख से अधिक हो गई, और पर्यटन में निरंतर वृद्धि हो रही है। मौजूदा सड़क नेटवर्क, जो मूल रूप से बहुत कम आबादी के लिए डिज़ाइन किया गया था, अब बढ़ते वाहनों के यातायात से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा है। वहीं, शिमला में पंजीकृत वाहनों की संख्या में 2005 से 2015 के बीच लगभग 50% से अधिक की वृद्धि हुई है। वाहनों की संख्या में यह वृद्धि, विशेष रूप से पर्यटन के मौसम में अधिक हो जाना जो लगातार ट्रैफिक जाम, सड़क रुकावटों और प्रदूषण में वृद्धि का कारण बन जाता है। विशेष रूप से, शहर के प्रमुख जंक्शन जैसे विकट्री टनल, लक्कड़ बाजार और संजौली में अक्सर गंभीर भीड़भाड़ पाई जाती है।

इन बढ़ते दबावों को दूर करने के लिए, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने कई उपाय शुरू किए हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख जिला सड़कों (एमडीआर) 66 और 67 पर सड़क चौड़ीकरण और सुधार परियोजना है। ये सड़कें निवासियों, पर्यटकों और माल परिवहन के लिए महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग हैं, लेकिन वे वर्तमान में बढ़ते यातायात की मात्रा को संभालने के लिए बहुत संकीर्ण हैं। प्रस्तावित परियोजना, जिसमें प्रमुख खंडों का चौड़ीकरण शामिल है, का उद्देश्य सड़क क्षमता

का विस्तार करके और यातायात प्रवाह में सुधार करके भीड़भाड़ को कम करना है। विशेष रूप से यह परियोजना दो प्रमुख मार्गों पर ध्यान केंद्रित करेगी: टूटी कंडी विभाजन से छोटा शिमला और संजौली चौक के माध्यम से संजौली ढली बाईपास जंक्शन तक का खंड, और विक्ट्री टनल से लक्कड़ बाजार जंक्शन और ढली के माध्यम से संजौली ढली तक की सड़क। इसके अतिरिक्त छोटा शिमला से कसुम्पटी सड़क पर तिब्बती स्कूल के पास पैदल मार्ग का निर्माण भी शामिल है। इन सड़कों को चौड़ा करने से आवाजाही में सुधार, यात्रा का समय कम होने और ड्राइवरों और पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षा में वृद्धि होने की उम्मीद है।

भूमि अधिग्रहण इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि इन सड़कों के विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है। इस अधिग्रहण प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों और संपत्ति मालिकों के साथ परामर्श शामिल होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विस्तार निवासियों को असंगत रूप से प्रभावित नहीं करता है। इसके अलावा, सरकार निर्माण चरण के दौरान नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र तथा पर्यावरणीय नुकसान को कम करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कुल मिलाकर, यह पहल शिमला के बुनियादी ढांचे को भविष्य की चुनौतियों के लिए अधिक लचीला बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के साथ इसकी अनूठी सांस्कृतिक और पर्यावरणीय विरासत को संरक्षित करने का प्रयास है। यह सड़क चौड़ीकरण/विस्तार परियोजना, वर्तमान गतिशीलता के मुद्दों को संबोधित करने के उद्देश्य से, आने वाले दशकों में शिमला के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक शहरी नियोजन प्रयासों के साथ भी जुड़ी हुई है।

1.1.1. अंतर-राज्यीय/अंतर्राष्ट्रीय पहलू

एमडीआर (एमडीआर) का तात्पर्य "प्रमुख जिला सड़क" से है, जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत एक विशिष्ट सड़क मार्ग है। एमडीआर 66 और 67 से जुड़ी सभी परियोजनाएं, जैसे कि शिमला शहर में वर्तमान परियोजना, इस श्रेणी के अंतर्गत सड़कों के लिए राज्य के नियमों के अनुसार प्रबंधित और विकसित की जाती हैं। प्रबंधन में भूमि अधिग्रहण जैसे विचार शामिल हैं जो यह सुनिश्चित करता है कि अन्य राज्यों या अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यह परियोजना शिमला शहर में स्थित है, जिसका प्रबंधन पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, जिसका अन्य राज्यों या देशों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता

है। इसलिए, सभी अंतरराज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं को ध्यान में रखा गया है, और प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण और विकास से कोई सीमा-पार समस्या उत्पन्न होने की उम्मीद नहीं है।

1.1.2. डेवलपर्स पृष्ठभूमि

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (एचपीपीडब्ल्यूडी) हिमाचल प्रदेश राज्य में बुनियादी ढांचे की योजना, निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार एक प्रमुख सरकारी एजेंसी है। इसमें सड़कों, पुलों और इमारतों का विकास और रखरखाव, राज्य भर में कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे का विकास सुनिश्चित करना शामिल है। एचपीपीडब्ल्यूडी राज्य की आर्थिक वृद्धि का समर्थन करने वाली परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुँच को बेहतर बनाने के लिए, विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण इलाकों में सड़क नेटवर्क को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। विभाग बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लागू करने और नियमों और मानकों का पालन करने के लिए अन्य राज्य और केंद्र सरकार के निकायों के साथ भी सहयोग करता है। आवश्यक बुनियादी ढाँचा और कनेक्टिविटी प्रदान करके पर्यटन, कृषि और अन्य व्यवसाय और सामाजिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए इसका काम महत्वपूर्ण है।

विभाग राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में सड़कों, पुलों, रोपवे और इमारतों - आवासीय और गैर-आवासीय दोनों - की योजना, निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त, विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार के तहत स्थानीय निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों और अन्य संस्थानों की ओर से इंजीनियरिंग परियोजनाओं को अंजाम देता है।

1.2 परियोजना का औचित्य और सार्वजनिक उद्देश्य

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सड़क नेटवर्क को शहर की आबादी और वाहनों की आवाजाही में तेज़ी से हो रही वृद्धि के कारण महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मूल रूप से यह एक छोटे से जनसांख्यिकीय क्षेत्र की सेवा के लिए डिज़ाइन किया गया, लेकिन अब बुनियादी ढाँचा बढ़ती माँग को पूरा करने में संघर्ष कर रहा है, जिससे लगातार भीड़भाड़ और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ पैदा हो रही हैं, खास तौर पर व्यस्त समय और पर्यटन के

मौसम के दौरान। यह भीड़भाड़ दैनिक जीवन को प्रभावित करती है, आर्थिक गतिविधियों में बाधा डालती है और आपातकालीन सेवाओं पर दबाव डालती है।

इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने एमडीआर 66 और 67 पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक प्रमुख सड़क सुधार परियोजना का प्रस्ताव दिया है। इस परियोजना का उद्देश्य मुख्य सड़क खंडों को चौड़ा और बेहतर बनाना है, विशेष रूप से टूटी कंडी विभाजन से संजौली-ढली बाईपास जंक्शन तक छोटा शिमला और संजौली चौक के माध्यम से और विकट्री टनल से संजौली-ढली तक लक्कड़ बाज़ार जंक्शन और ढली के माध्यम से मार्गों को लक्षित करना। इसके अतिरिक्त तिब्बती स्कूल, छोटा शिमला-कसुम्पटी रोड के पास पैदल यात्री पथ का निर्माण किया जाएगा। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य यातायात की भीड़भाड़ को कम करना, सड़क सुरक्षा में सुधार करना और समय परिवहन दक्षता को बढ़ाना है।

परियोजना के लिए मुख्य तर्क:

- यातायात की भीड़भाड़ को कम करना: सड़क नेटवर्क का विस्तार करने से यातायात की अड़चनों को कम करने और वाहनों के प्रवाह को आसान बनाने में मदद मिलेगी, खासकर पीक ऑवर्स और उच्च यातायात पर्यटन समय अवधि के दौरान।
- बढ़ी हुई सड़क सुरक्षा: सड़कों को बेहतर बनाने से बढ़ते यातायात को संभालने के लिए बेहतर बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराकर सुरक्षा मुद्दों का समाधान किया जाएगा, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना कम हो जाएगी।
- बेहतर कनेक्टिविटी: परियोजना शहर के भीतर पहुँच में सुधार करेगी, जिससे प्रमुख क्षेत्रों और आवश्यक सेवाओं के बीच अधिक कुशल यात्रा की सुविधा मिलेगी।
- सतत शहरी विकास के लिए समर्थन: परियोजना शिमला के विकास में उभरती हुई मांगों को पूरा करने के लिए बुनियादी ढाँचे का आधुनिकीकरण करके सतत शहरी विकास का समर्थन करती है।
- आर्थिक और सामाजिक लाभ: परिवहन में सुधार करके, परियोजना से स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने, पर्यटन को बढ़ावा मिलने और निवासियों की समय भलाई में योगदान मिलने की उम्मीद है।

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार (आरटीएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2013 की धारा 2, उप-धारा 1 (बी) के अनुरूप, जो इस तरह की बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को सार्वजनिक उद्देश्य के तहत वर्गीकृत करता है, सड़क चौड़ीकरण की पहल उचित है।

परिणामस्वरूप, हिमाचल प्रदेश भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक प्रभाव आकलन और सहमति) नियम, 2015 के नियम 3 के तहत भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) की आवश्यकता होती है। यह आकलन सुनिश्चित करेगा कि परियोजना को उसके सामाजिक प्रभावों और हितधारकों की चिंताओं पर पूर्ण विचार करते हुए क्रियान्वित किया जाए। कुल मिलाकर, प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण और सुधार परियोजना शिमला की परिवहन चुनौतियों का समाधान करने, इसके विकास का समर्थन करने और इसके निवासियों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है।

1.3 परियोजना विवरण

प्रस्तावित अधिग्रहण में शिमला शहर में दो प्रमुख मार्गों; टूटी कंडी विभाजन से संजौली-ढल्ली बाईपास जंक्शन तक और विकट्री टनल से लक्कड़ बाजार जंक्शन और ढल्ली होते हुए संजौली चौक पर भूमि और भवन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, छोटा शिमला में एक और खंड है, जहाँ तिब्बती स्कूल के पास छोटा शिमला-खास के राजस्व क्षेत्र में निजी भूमि/दुकानें पैदल पथ के निर्माण के लिए अधिग्रहित की जा रही हैं। परिणामस्वरूप, इन विशिष्ट क्षेत्रों के लिए एक सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एसआईए) आयोजित किया गया है। तालिका 1-1 परियोजना विवरण दिखाती है।

तालिका 1-1 शिमला, हिमाचल प्रदेश में एमडीआर 66 और एमडीआर-67 की परियोजना विवरण

क्रम संख्या	विवरण	प्रस्तावित विवरण
	परियोजना का नाम	सड़क चौड़ीकरण/विकास परियोजना एमडीआर-66 (टूटी कंडी से संजौली वाया छोटा शिमला) और एमडीआर-67 (विकट्री टनल से ढली चौक वाया लक्कड़ बाजार)। तिब्बती स्कूल, छोटा शिमला के पास पैदल पथ का निर्माण।
	अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल	20868-58 वर्गमीटर/डेसीमीटर

	स्थान	प्रस्तावित भूमि एमडीआर-66 और एमडीआर-67 के साथ-साथ स्थित है, जो शिमला शहर के प्रमुख मार्गों को कवर करती है, और पैदल पथ के निर्माण के लिए छोटा शिमला में तिब्बती स्कूल के पास है।
--	-------	---

1.3.1. परियोजना का आकार

शिमला शहर में एमडीआर 66 और 67 परियोजना दो प्रमुख मार्गों पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य शहर के भीतर यातायात प्रवाह और संपर्क में सुधार करना है। ये मार्ग हैं:

- टुटीकंडी विभाजन से संजौली ढली बाईपास जंक्शन तक छोटा शिमला और संजौली चौक।
- विकट्री सुरंग से संजौली-ढली तक लक्कड़ बाजार जंक्शन और ढली।

ये दोनों सड़कें शहर के चारों ओर एक गोलाकार मार्ग बनाती हैं, जो गुब्बारे जैसी आकृति जैसा दिखता है, जो शिमला शहर के प्रमुख स्थानों के बीच संपर्क को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त, इस परियोजना में छोटा शिमला-कसुम्पटी रोड में तिब्बती स्कूल के पास पैदल यात्री पथ का निर्माण भी शामिल है, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में पैदल यात्रियों के लिए पहुँच और सुरक्षा में सुधार करना है।

इस परियोजना के तहत अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित कुल भूमि 20,882.53 वर्ग मीटर या 2.0883 हेक्टेयर है, जिसमें 12 गाँव (राजस्व दस्तावेजों में उल्लिखित) और 378 खसरा नंबर शामिल हैं। अधिग्रहित भूमि का उपयोग सड़कों को चौड़ा करने और यातायात प्रवाह को सुचारू बनाने तथा पैदल यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जाएगा। यह परियोजना शिमला की बढ़ती परिवहन चुनौतियों को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो यह सुनिश्चित करती है कि शहर निवासियों और आगंतुकों के लिए समान रूप से सुलभ और सुरक्षित बना रहे।

1.3.2. स्थान

यह परियोजना शिमला शहर के आसपास स्थित है, जिसमें प्रमुख सड़क खंडों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें टुटीकंडी विभाजन से संजौली और ढली तक का मार्ग शामिल है, जो

लक्कड़ बाजार जंक्शन और छोटा शिमला दोनों तरफ से होकर गुजरता है। ये मार्ग शहर के भीतर शहरी गतिशीलता और संपर्क को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

1.3.2.1 परियोजना क्षेत्र तक पहुँच

परियोजना क्षेत्र एक व्यापक सड़क नेटवर्क द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। शिमला, हिमाचल प्रदेश में एक प्रमुख पर्यटक और प्रशासनिक केंद्र होने के नाते, परिवहन के विभिन्न साधनों के माध्यम से आसानी से पहुँचा जा सकता है। यह शहर चंडीगढ़ से लगभग 115 किमी दूर है और यूनेस्को की विश्व धरोहर मार्ग कालका-शिमला रेलवे के माध्यम से भी पहुँचा जा सकता है। निकटतम हवाई अड्डा जुब्बड़हट्टी है, जो शिमला से लगभग 20 किमी दूर स्थित है, जो निवासियों और आगंतुकों दोनों के लिए संपर्क को और बढ़ाता है।

1.3.2.2 भौगोलिक संरचना और भू-आकृति विज्ञान

शिमला शहर कई पहाड़ियों और संपर्क रिज पर स्थित है। प्रमुख पहाड़ियों में जाखू (8,050 फीट), प्रॉस्पेक्ट हिल (7,140 फीट), ऑब्ज़र्वेटरी हिल (7,050 फीट), एलीसियम हिल (7,400 फीट) और समर हिल (6,900 फीट) शामिल हैं। शिमला का नगरपालिका शहर 30° 6' उत्तरी अक्षांश और 77° 11' पूर्वी देशांतर पर स्थित है, जिसकी औसत समुद्र तल (MSL) से 2,397.59 मीटर की औसत ऊँचाई है। यह शहर एक छोर से दूसरे छोर तक 9.2 किमी से अधिक अनियमित अर्धचंद्राकार आकार में फैला हुआ है, जो कुल 19.55 वर्ग किमी क्षेत्र को कवर करता है। शिमला भौगोलिक रूप से अद्वितीय है; यदि रिज मैदान पर उत्तरी ढलान पर पानी डाला जाता है, तो यह सतलुज नदी के माध्यम से अरब सागर की ओर बहता है, जबकि दक्षिणी ढलान पर डाला गया पानी यमुना नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में बहता है।

1.3.2.3 भूकंपीयता

शिमला शहर IS-1893 के अनुसार एक भूकंपीय बेल्ट (भूकंपीय क्षेत्र IV) में स्थित है।

1.3.3. क्षमता और उत्पादन

इस परियोजना का उद्देश्य टूटीकंडी विभाजन से संजौली और ढली तक मौजूदा सड़क नेटवर्क को चौड़ा करना है, जो लक्कड़ बाजार जंक्शन और छोटा शिमला दोनों से होकर गुजरेगा, ताकि

यातायात की भीड़ को कम किया जा सके और यातायात का सुचारु प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके।

1.3.4. परियोजना लागत और जोखिम

संबंधित एजेंसी ने परियोजना की लागत साझा नहीं की है, जबकि पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा के लिए उचित उपाय नहीं किए जाने पर पर्यावरण क्षरण और पारिस्थितिकी संबंधी चिंताओं के साथ-साथ वनस्पतियों के नुकसान का जोखिम है। यदि निष्पादन चरण के दौरान सावधानी नहीं बरती गई तो जल निकासी नेटवर्क में व्यवधान का जोखिम है, जिसे भविष्य में प्राकृतिक धाराओं के तल स्तर को ऊपर उठाने के साथ कम किया जा सकता है।

1.4 विकल्पों की जांच

चूंकि प्रस्ताव यातायात के सुचारु प्रवाह को आसान बनाने और शिमला शहर के निवासियों के जीवन को आसान बनाने के लिए मौजूदा सड़क की चौड़ाई को चौड़ा करने का है, इसलिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है, इसलिए कोई विकल्प नहीं दिया गया है।

1.5 परियोजना निर्माण के चरण

टुटीकंडी विभाजन से संजौली ढली बाईपास जंक्शन तक छोटा शिमला और संजौली चौक।

विकट्री सुरंग से संजौली ढली तक लक्कड़ बाजार जंक्शन और ढली।

तिब्बती स्कूल के पास छोटा शिमला-कसुम्पटी सड़क पर पैदल पथ का निर्माण।

1.6 मुख्य डिजाइन विशेषताएँ, आकार और सुविधाओं के प्रकार

संबंधित एजेंसी द्वारा साझा नहीं किया गया

1.7 कार्यबल की आवश्यकताएँ

परियोजना के निष्पादन चरण के दौरान जनशक्ति की आवश्यकता होगी, हालाँकि अभी तक मानव दिवसों की गणना नहीं की गई है।

1.8 पर्यावरण प्रभाव आकलन और तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट का विवरण

संबंधित एजेंसी द्वारा ऐसी कोई रिपोर्ट प्रदान नहीं की गई है।

1.9 लागू कानून और नीतियाँ

भारत में सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण विशिष्ट कानूनी ढाँचों द्वारा शासित होता है जो पारदर्शिता और सामुदायिक भागीदारी पर जोर देते हैं। इनमें से प्रमुख हैं भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार (RTFCTLARR) अधिनियम, 2015, और हिमाचल प्रदेश आरटीएफसीटीएलएआरआर नियम, 2015, जो सामाजिक प्रभाव आकलन और सामुदायिक परामर्श के लिए अनिवार्य प्रक्रियाओं को रेखांकित करते हैं, जैसा कि निम्नलिखित अनुभागों में विस्तृत है

1.9.1. सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन की तैयारी

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार (RTFCTLARR) अधिनियम, 2015, धारा 4 के तहत, यह निर्धारित करता है कि जब भी उपयुक्त सरकार सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण करने का प्रस्ताव करती है, तो उसे प्रभावित क्षेत्र के भीतर गाँव या नगरपालिका स्तर पर संबंधित पंचायत या वार्ड से परामर्श करना आवश्यक है। यह परामर्श एस०आई०ए० अध्ययन करने के लिए एक शर्त है, जिसे स्थानीय निकायों के सहयोग से किया जाना चाहिए। एस०आई०ए० आयोजित करने की प्रक्रिया, विधियों और प्रारंभ तिथि सहित, सरकार द्वारा एक आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से निर्दिष्ट की जानी है। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश आरएफसीटीएलएआरआर नियम, 2015 का नियम 3(1) राज्य के भीतर अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त प्रक्रियात्मक विवरण प्रदान करता है। इस नियम के अनुसार, राज्य सरकार को नियमों के फॉर्म-1 के भाग-बी में निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए एस०आई०ए० शुरू करने के लिए अधिसूचना जारी करना अनिवार्य है। यह अधिसूचना हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रसारित की जानी चाहिए और संबंधित पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम को सुलभ कराई जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, अधिसूचना की प्रतियां जिला कलेक्टर, उप-मंडल मजिस्ट्रेट और तहसील के कार्यालयों में उपलब्ध

होनी चाहिए। व्यापक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए, अधिसूचना को प्रभावित क्षेत्र में प्रसारित होने वाले कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना चाहिए और प्रभावित क्षेत्रों के भीतर विशिष्ट स्थानों पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। अधिसूचना को व्यापक पहुंच और पारदर्शिता के लिए राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाना आवश्यक है। ये प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पारदर्शी रूप से और ऐसी पहलों से प्रभावित स्थानीय समुदायों की चिंताओं और सुझावों को ध्यान में रखते हुए संचालित की जाती है।

1.9.2. भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया

सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पारदर्शिता, सामुदायिक भागीदारी और कानूनी विधानों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किए गए चरणों की एक श्रृंखला द्वारा शासित होती है। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित प्रमुख चरणों की रूपरेखा दी गई है:

- सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा या शहरी क्षेत्रों में समकक्ष निकायों के परामर्श से सामा एस०आई०ए० अध्ययन करके भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करती है।
- एस०आई०ए० के बाद, रिपोर्ट का मूल्यांकन एक विशेषज्ञ समूह द्वारा किया जाता है जिसमें दो गैर-आधिकारिक सामाजिक वैज्ञानिक, दो पुनर्वास विशेषज्ञ और परियोजना से संबंधित एक तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होते हैं।
- मूल्यांकित एस०आई०ए०रिपोर्ट की फिर एक समिति द्वारा समीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण आवश्यक शर्तों को पूरा करता है।
- भूमि अधिग्रहण के लिए सरकार की मंशा को दर्शाने वाली एक प्रारंभिक अधिसूचना एस०आई०ए०रिपोर्ट के मूल्यांकन के 12 महीने के भीतर जारी की जानी चाहिए।
- फिर सरकार परियोजना के लिए आवश्यक भूमि की सटीक सीमा निर्धारित करने के लिए एक सर्वेक्षण करती है।
- अधिग्रहण प्रक्रिया पर किसी भी आपत्ति की सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाती है। यदि सरकार सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त है, तो भूमि अधिग्रहण के लिए एक औपचारिक घोषणा की जाती है।
- इस घोषणा के प्रकाशन के बाद, सरकार भूमि अधिग्रहण के साथ आगे बढ़ती है।
- प्रारंभिक अधिसूचना की तारीख से, अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने तक निर्दिष्ट भूमि से जुड़े किसी भी लेन-देन की अनुमति नहीं है।

1.9.3. भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (RTFCTLARR अधिनियम, 2013) 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम को प्रतिस्थापित करने के लिए अधिनियमित किया गया था, जो औपनिवेशिक काल से उत्पन्न एक कानून था। आरटीएफसीटीएलएआरआर अधिनियम पिछले कानून की महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण सुधार का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका उद्देश्य भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के आधुनिकीकरण और प्रभावशीलता को बढ़ाना है। अधिनियम भूमि मालिकों के हितों को औद्योगीकरण, अचल संपत्ति और बुनियादी ढांचे के विकास की जरूरतों के साथ संतुलित करना चाहता है, जबकि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। आरटीएफसीटीएलएआरआर अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता उचित मुआवजे के प्रावधान के साथ-साथ उन व्यक्तियों के अनिवार्य पुनर्वास और पुनर्स्थापन पर जोर देना है जिनकी भूमि अधिग्रहित की जाती है। उल्लेखनीय रूप से, अधिनियम में भूमि मालिकों के लिए बढ़ा हुआ मुआवज़ा निर्धारित किया गया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बाज़ार मूल्य से चार गुना और शहरी क्षेत्रों में बाज़ार मूल्य से दोगुना तक हो सकता है, विशेष रूप से उन मामलों में जहाँ सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्देश्यों या सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहित की जाती है। अधिनियम को भूमिधारकों और अन्य प्रभावित पक्षों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए एक आवश्यक और लाभकारी उपाय के रूप में व्यापक रूप से मान्यता दी गई है।

1.9.3.1 आर.टी.एफ.सी.टी.एल.ए.आर.आर. अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

आर.टी.एफ.सी.टी.एल.ए.आर. अधिनियम भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आर.एंड.आर.) दोनों को नियंत्रित करने वाले महत्वपूर्ण प्रावधानों को प्रस्तुत करता है। पिछले कानून से प्रमुख परिवर्तनों में निम्नलिखित क्षेत्रों में सुधार शामिल हैं:

- भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया, जो अब अधिक पारदर्शिता और सामुदायिक भागीदारी पर जोर देती है;

- भूमि अधिग्रहण से विस्थापित व्यक्तियों के अधिकार, मजबूत सुरक्षा और सहायता सुनिश्चित करना;
- मुआवजे की गणना करने की विधि, जिसे प्रभावित भूमि मालिकों को उचित और बढ़ा हुआ मुआवजा प्रदान करने के लिए संशोधित किया गया है; और
- सभी भूमि अधिग्रहणों के लिए आर.एंड.आर. की अनिवार्य आवश्यकता, जो यह सुनिश्चित करती है कि विस्थापित व्यक्तियों का पर्याप्त रूप से पुनर्वास और पुनर्स्थापन हो।

1.9.3.2 भूमि मालिकों को मुआवजा

आर.टी.एफ.सी.टी.एल.ए.आर. अधिनियम, 2013 के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा अधिनियम के भीतर निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। ये प्रावधान मुआवजे की गणना के लिए एक रूपरेखा स्थापित करते हैं जिसका उद्देश्य भूमि स्वामियों के लिए उचित और पर्याप्त पारिश्रमिक सुनिश्चित करना है, जो भूमि के मूल्य और अधिनियम में उल्लिखित किसी भी अतिरिक्त अधिकार को दर्शाता है।

1.9.3.3 पुनर्वास और पुनर्स्थापन की प्रक्रिया

पुनर्वास और पुनर्स्थापन अलग-अलग लेकिन परस्पर जुड़ी हुई प्रक्रियाएँ हैं। पुनर्स्थापन से तात्पर्य प्रभावित व्यक्तियों के भौतिक पुनर्वास से है, जो अक्सर एक नई पुनर्वास कॉलोनी में होता है, जबकि पुनर्वास उनकी आजीविका की बहाली से संबंधित है। साथ में, इन प्रक्रियाओं का उद्देश्य व्यापक भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बहाली हासिल करना है। आरटीएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के तहत, प्रत्येक भूमि अधिग्रहण के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन आयोजित किया जाना चाहिए। अधिग्रहण के लिए प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के बाद, प्रक्रिया की देखरेख के लिए एक प्रशासक नियुक्त किया जाता है। यह प्रशासक एक सर्वेक्षण करता है और एक आर.एंड.आर. योजना विकसित करता है, जिसकी फिर शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों द्वारा समीक्षा की जाती है। योजना पर किसी भी आपत्ति को प्रशासक द्वारा संबोधित किया जाता है, जो बाद में कलेक्टर के लिए एक रिपोर्ट तैयार करता है। कलेक्टर योजना की समीक्षा करता है और इसे अनुमोदन के लिए आर.एंड.आर. आयुक्त को भेजता है। आयुक्त की स्वीकृति के बाद, सरकार एक घोषणा जारी करती है जिसमें पुनर्वास और पुनर्वास के लिए निर्दिष्ट क्षेत्रों को निर्दिष्ट किया जाता है। इसके बाद प्रशासक योजना को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि आयुक्त स्थापित प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए इसके कार्यान्वयन की निगरानी करता है।

1.9.4. हिमाचल प्रदेश आरटीएफसीटीएलएआरआर नियम 2015

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक प्रभाव आकलन और सहमति) नियम, 2015, 9 अप्रैल, 2015 को अधिसूचित किए गए थे, और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्या 30) की धारा 112 के अनुसार हिमाचल प्रदेश के राजपत्र (ई-गजट) में प्रकाशित किए गए थे। ये नियम पूरे हिमाचल प्रदेश राज्य में लागू हैं।

केंद्रीय अधिनियम 2013 के आधार पर हिमाचल प्रदेश आरटीएफसीटीएलएआरआर नियम, 2015 राज्य में सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) आयोजित करने के लिए प्रक्रियात्मक ढांचा स्थापित करते हैं। इन नियमों की मुख्य विशेषताएं शामिल हैं: (ए) फॉर्म II और III के अनुसार एस०आई०ए और सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजनाओं (एसआईएमपी) का संचालन; (बी) सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करने की आवश्यकता; और (सी) सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता। इनमें से प्रत्येक पहलू का बाद के खंडों में विस्तार से वर्णन किया गया है।

1.9.4.1 एस०आई०ए और एसआईएमपी का संचालन

फॉर्म II: सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) रिपोर्ट आकलन शुरू होने से छह महीने के भीतर राज्य सरकार को प्रस्तुत की जानी चाहिए। इस रिपोर्ट में प्रभावित परिवारों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का विस्तृत विवरण शामिल होना चाहिए, जिसे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो। फॉर्म II एस०आई०ए रिपोर्ट के लिए आवश्यक संरचना और सामग्री को निर्दिष्ट करता है।

फॉर्म III: सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एसआईएमपी) परियोजना के प्रभावों को संबोधित करने के लिए आवश्यक उपचारात्मक उपायों की रूपरेखा तैयार करती है। इस योजना को एस०आई०ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए और एसआईएमपी में शामिल की जाने वाली सामग्री पर दिशानिर्देश प्रदान करता है।

फॉर्म II और III इस रिपोर्ट के परिशिष्ट में विस्तार से दिए गए हैं।

1.9.4.2 जन सुनवाई का आयोजन

- सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) के मुख्य निष्कर्षों को प्रस्तुत करने, इन निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने तथा अंतिम रिपोर्ट में शामिल करने के लिए अतिरिक्त जानकारी और दृष्टिकोण एकत्र करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में जन सुनवाई आयोजित की जानी आवश्यक है।
- जन सुनवाई की तिथि और स्थान की घोषणा कम से कम तीन सप्ताह पहले की जानी चाहिए तथा व्यापक रूप से प्रचारित किया जाना चाहिए। यह प्रस्तावित अधिग्रहण स्थल के पांच किलोमीटर के दायरे में सभी गांवों में सार्वजनिक अधिसूचनाओं और पोस्टरों, स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापनों, रेडियो प्रसारणों, ग्राम पंचायत या नगर निगम वार्ड प्रतिनिधियों से सीधे संवाद तथा राज्य सरकार की वेबसाइट पर जानकारी अपलोड करके किया जाना चाहिए।
- सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एसआईएमपी) तथा एस०आई०ए रिपोर्ट दोनों को प्रभावित क्षेत्रों में गांव या वार्ड स्तर पर संबंधित पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम को हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ये दस्तावेज जिला कलेक्टर, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट और तहसीलदारों के कार्यालयों में भी उपलब्ध होने चाहिए तथा राज्य सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने चाहिए।
- जन सुनवाई में अधियाचना करने वाले निकाय, नामित भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन पदाधिकारी, जन प्रतिनिधि, स्थानीय स्वैच्छिक संगठन और मीडिया कर्मियों के प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए।
- जन सुनवाई की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग और प्रतिलेखन किया जाना चाहिए। रिकॉर्डिंग और प्रतिलेखन दोनों को अंतिम एस०आई०ए रिपोर्ट और एसआईएमपी के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

1.9.4.3 सहमति

राज्य सरकार, संबंधित जिला कलेक्टर के माध्यम से, प्रभावित भूमि मालिकों से पूर्व सहमति प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार है, जैसा कि फॉर्म-IV के भाग-ए में प्रलेखित है। साथ ही, राज्य सरकार को प्रभावित क्षेत्रों में शीर्षक और अन्य राजस्व रिकॉर्ड सहित भूमि रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि सहमति प्रक्रिया और उसके बाद भूमि अधिग्रहण शुरू करने के लिए भूमि मालिकों, भूमि पर कब्जा करने वालों और अन्य प्रासंगिक व्यक्तियों के नामों की सही पहचान की जाती है।

प्रभावित भूमि मालिकों की सहमति

आर०एफ०सी०टी०एल०ए०आर०आर० अधिनियम, 2013 के तहत, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पी०पी०पी०) और निजी कंपनियों द्वारा सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहित किए जाने पर सहमति अनिवार्य है। हालाँकि, चूँकि एमडीआर -66 और एमडीआर -67 पर सड़क विकास परियोजना उपयुक्त सरकारी प्राधिकरण द्वारा की जा रही है, इसलिए इस अध्ययन के लिए सहमति की आवश्यकता नहीं है। आर०एफ०सी०टी०एल०ए०आर०आर० अधिनियम, 2013 की धारा 2(2) में प्रावधान है: "भूमि अधिग्रहण, सहमति, मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्स्थापन से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान तब भी लागू होंगे जब उपयुक्त सरकार निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए भूमि का अधिग्रहण करती है: क) सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए, जहां भूमि का स्वामित्व सरकार के पास रहता है, उप-धारा (1) में परिभाषित सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए। ख) उप-धारा (1) में परिभाषित सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए निजी कंपनियों के लिए।"

2. सामाजिक प्रभाव आकलन की टीम संरचना, दृष्टिकोण, कार्यप्रणाली और अनुसूची

यह अध्याय प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण परियोजना के सामाजिक प्रभाव आकलन (एस०आई०ए०) के संचालन के लिए अपनाए गए कार्यप्रणाली दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यह आकलन टीम की संरचना, प्रत्येक सदस्य की विशिष्ट विशेषज्ञता और परियोजना के सामाजिक निहितार्थों का मूल्यांकन करने के लिए नियोजित व्यवस्थित प्रक्रियाओं का विवरण देता है। कठोर कार्यप्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि सभी प्रासंगिक सामाजिक कारकों की गहन जांच की जाए, जिससे सूचित निर्णय लेने के लिए एक ठोस आधार प्रदान किया जा सके।

2.1 टीम का विवरण

तालिका 2-1 अध्ययन के संचालन के लिए जिम्मेदार एस०आई०ए० टीम की संरचना प्रस्तुत करती है। टीम का प्रत्येक सदस्य अपने संबंधित क्षेत्र में एक मान्यता प्राप्त विशेषज्ञ है, जो इसी तरह के कई पिछले अध्ययनों से व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता लाता है। टीम की बहु-विषयक प्रकृति सामाजिक प्रभावों का आकलन करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित करती है, जिसमें प्रत्येक विशेषज्ञ अध्ययन के सफल निष्पादन के लिए महत्वपूर्ण विशेष ज्ञान का योगदान देता है।

तालिका 2-2 में उन क्षेत्र सर्वेक्षणकर्ताओं की सूची दी गई है जिन्होंने सामाजिक प्रभाव आकलन के लिए प्राथमिक सर्वेक्षण में सक्रिय रूप से भाग लिया। ये सर्वेक्षणकर्ता डेटा संग्रह प्रक्रिया के अभिन्न अंग थे, जिन्होंने सटीक और व्यापक जानकारी एकत्र करने के लिए स्थानीय समुदायों से सीधे संपर्क किया। उनके प्रयासों ने प्राथमिक डेटा की मजबूती सुनिश्चित की, जो आकलन के निष्कर्षों की वैधता के लिए महत्वपूर्ण है।

2.2 कार्यप्रणाली और प्रयुक्त उपकरणों का विवरण और औचित्य

यह खंड शिमला शहर में एमडीआर-66 और एमडीआर-67 पर सड़क विकास, रखरखाव और चौड़ीकरण परियोजना के लिए एस०आई०ए० के संचालन में प्रयुक्त कार्यप्रणाली और उपकरणों

की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। चुना गया दृष्टिकोण प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के सामाजिक परिणामों का व्यवस्थित रूप से मूल्यांकन करने, प्रासंगिक कानूनी ढाँचों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और प्रभावित समुदायों पर संभावित प्रभावों की व्यापक समझ प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

क्र. सं.	नाम	शैक्षिक योग्यता	लिंग	विशेषज्ञता/जिम्मेदारी
1	इंजीनियर तरुण गुप्ता (टीम लीडर)	बी.टेक (एजी), पीजी डीपीएम, पीजी डीएमएम	पुरुष	- वरिष्ठ पर्यावरण अधिकारी, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (सेवानिवृत्त) - विशेषज्ञ ईआईए एवं एसआईए, रिपोर्ट लेखन
2	मंगत चौहान	पीजी पीएम एंड आईआर, पीजी मार्केटिंग मैनेजमेंट	पुरुष	- प्रभाव आकलन एवं सामुदायिक लामबंदी (परियोजना समन्वयक)
3	रमन कुमार	पीएच.डी.	पुरुष	- सर्वेक्षण एवं डेटा विश्लेषण, प्रभाव आकलन एवं सामुदायिक लामबंदी में विशेषज्ञ
4	एम.आर. शर्मा	सामाजिक कार्य में स्नातक	पुरुष	- सर्वेक्षण एवं सांख्यिकीय शोधकर्ता
5	संगीता	एम.ए	महिला	- सर्वेक्षण एवं सांख्यिकीय शोधकर्ता
6	निशिमा भारद्वाज	एम.ए	महिला	- अन्वेषक एवं लिंग विशेषज्ञ

तालिका 2-1 सामाजिक प्रभाव आँकलन टीम संरचना और विशेषज्ञता

तालिका 2-2 सामाजिक प्रभाव आँकलन के लिए क्षेत्र सर्वेक्षकों की सूची

क्र. सं.	नाम	शैक्षिक योग्यता	लिंग
1.	कपूर शर्मा	पीजी	पुरुष
2.	मनीष शर्मा	स्नातक	पुरुष
3.	प्रोमिला शर्मा	स्नातक	महिला
4.	पुष्प राज	पीजी	पुरुष

2.2.1. लक्ष्य

अध्ययन का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन और सहमति) नियम, 2015 के अनुसार एस०आई०ए० करना है, विशेष रूप से शिमला शहर में एमडीआर-66 और एमडीआर-67 पर सड़क विकास, रखरखाव और चौड़ीकरण परियोजना के लिए।

2.2.2. उद्देश्य

अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1. यह मूल्यांकन करना कि क्या प्रस्तावित अधिग्रहण आरटीएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 2 के तहत सूचीबद्ध मानदंडों के अनुसार सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति करता है।
2. प्रभावित परिवारों और विस्थापित होने वाले परिवारों की संख्या का अनुमान लगाना।
3. प्रस्तावित अधिग्रहण से प्रभावित होने वाली भूमि, सार्वजनिक और निजी, मकान, बस्तियाँ और अन्य सामान्य संपत्तियों की सीमा।
4. क्या अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमा परियोजना के लिए आवश्यक न्यूनतम सीमा है।
5. क्या वैकल्पिक स्थानों पर भूमि अधिग्रहण पर विचार किया गया है और इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया है।
6. परियोजना के सामाजिक प्रभावों, उन्हें संबोधित करने की प्रकृति और लागत का अध्ययन, और परियोजना की समग्र लागतों पर इन लागतों का प्रभाव बनाम लाभ।
7. एचपी आरटीएफसीटीएलएआरआर नियम, 2015 के फॉर्म-II के अनुसार प्रभावित क्षेत्र और पुनर्वास स्थल (यदि कोई हो) की सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक रूपरेखा तैयार करना।

8. एचपी आरटीएफसीटीएलएआरआर नियम, 2015 के फॉर्म III के अनुसार सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना तैयार करना।

2.2.3. दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली

सामाजिक प्रभाव आकलन करने और एस० आई० एम० पी० तैयार करने के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली का वर्णन नीचे किया गया है। एस०आई०ए को आरटीएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 और एचपी आरटीएफसीटीएलएआरआर नियम, 2015 के अनुसार तैयार किया गया है। नीचे दिया गया चित्र प्रवाह चार्ट के रूप में एस०आई०ए अध्ययन की कार्यप्रणाली प्रस्तुत करता है। एस०आई०ए अध्ययन करने और एसआईएमपी तैयार करने की प्रक्रिया/पद्धति

1. साहित्य समीक्षा

- भारत में कमजोर समूह - स्थिति, योजनाएं, भारत का संविधान (भारत में कमजोर समूह)।
- मियां गोवर्धन सिंह द्वारा शिमला अतीत और वर्तमान
- शिमला विकास योजना का प्रारूप

2. परामर्श और क्षेत्र का दौरा

- हितधारकों की पहचान (प्राथमिक और द्वितीयक डेटा)
- क्षेत्र का दौरा (साइट का दौरा)
- हितधारकों के साथ परामर्श

3. डेटा संग्रह

- द्वितीयक डेटा (राजस्व विभाग और पीडब्ल्यूडी सर्वेक्षण चित्र)

4. प्राथमिक डेटा (प्रश्नावली और एफजीडी, क्षेत्र का दौरा) 35% नमूना सर्वेक्षण आयोजित किया गया और जानकारी प्राप्त करने के लिए पूर्व-डिज़ाइन किए गए प्रश्नावली का उपयोग किया गया।

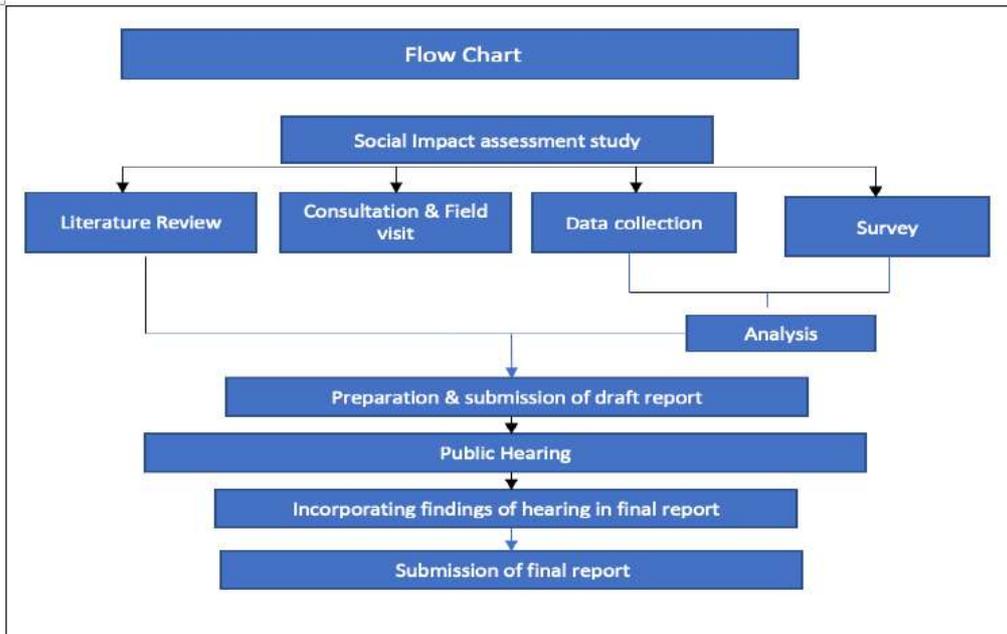
5. एकत्र किए गए डेटा का विश्लेषण

- विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों का गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण। एकत्र किए गए प्राथमिक और द्वितीयक डेटा का विश्लेषण
- एफजीडी से निकाले गए निष्कर्ष
- हितधारक परामर्श से निकाले गए निष्कर्ष
- साइट सर्वेक्षण से अवलोकन

1. मसौदा रिपोर्ट

1.1.1. कार्यप्रणाली का औचित्य

एस.आई.ए. एक समयबद्ध अध्ययन है और यह उन लोगों के हितों से संबंधित है जो आगामी परियोजना के लिए अधिग्रहित की जा रही भूमि पर आर्थिक, और सामाजिक रूप से निर्भर हैं। इसलिए, छोटा शिमला-कसुम्पटी सड़क पर तिब्बती स्कूल के पास पैदल पथ के निर्माण के साथ-साथ एमडीआर 66 और एमडीआर 67 के भूमि चौड़ीकरण के लिए मानवीय, भागीदारीपूर्ण, सूचित और पारदर्शी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अध्ययन करने के लिए उपरोक्त पद्धति को अपनाया गया है। यह कार्यप्रणाली ऐसे प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त प्रावधानों की रक्षा करती है और यह सुनिश्चित करती है कि अधिग्रहण का संचयी परिणाम यह होना चाहिए कि प्रभावित व्यक्ति विकास भागीदार बनें, जिससे अधिग्रहण के बाद उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हो।



आकृति Error! No text of specified style in document.-1 एमडीआर 66 और 67 के चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण में सामाजिक प्रभाव आँकलन आयोजित करने के लिए प्रवाह चार्ट

1.1.1.1 एस.आई.ए. के लिए परामर्श किए जाने वाले हितधारकों की पहचान

इस परियोजना से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले हितधारकों की एक व्यापक सूची तैयार की गई और उन्हें तीन व्यापक समूहों में वर्गीकृत किया गया:

2.2.4.1 एस.आई.ए. के लिए परामर्श किए जाने वाले हितधारकों की पहचान

इस परियोजना से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले हितधारकों की एक व्यापक सूची तैयार की गई और उन्हें तीन व्यापक समूहों में वर्गीकृत किया गया:

- **प्राथमिक हितधारक:** इनमें अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के शीर्षकधारक, उनके परिवार और अधिग्रहित की जा रही भूमि पर किसी भी प्रकार की निर्भरता वाले अन्य लोग शामिल हैं।
- **द्वितीयक हितधारक:** इस समूह में व्यावसायिक संस्थाएँ, नागरिक समाज, गैर सरकारी संगठन और स्थानीय निवासी शामिल हैं जो अधिग्रहण से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो सकते हैं।
- **संस्थागत हितधारक:** पंचायत, जिला आयुक्त कार्यालय और स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों जैसे सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थान इस श्रेणी में आते हैं।

हितधारकों की पहचान के बाद, एक डेस्क समीक्षा आयोजित की गई, जिसमें आरटीएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013, एचपी आरटीएफसीटीएलएआरआर नियम, 2015, जिला जनगणना डेटा और अन्य प्रासंगिक सरकारी और गैर-सरकारी स्रोतों जैसे दस्तावेजों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस समीक्षा से परियोजना क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली तथा एस.आई.ए. के आगामी चरणों के बारे में जानकारी मिली।

2.3 सामाजिक प्रभाव आकलन के लिए जानकारी एकत्र करने के उपकरण

एस०आई०ए के लिए डेटा संग्रह में संभावित सामाजिक प्रभावों की व्यापक समझ सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक और द्वितीयक दोनों स्रोत शामिल थे। उपयोग किए गए उपकरण और विधियाँ नीचे विस्तृत हैं:

1. द्वितीयक स्रोतों से डेटा:

- द्वितीयक डेटा जनगणना रिपोर्ट, सांख्यिकीय पुस्तिकाओं और अन्य प्रासंगिक साहित्य से एकत्र किया गया था। यह जानकारी प्राथमिक डेटा को पूरक बनाती है और परियोजना क्षेत्र के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संदर्भ की आधारभूत समझ प्रदान करती है।

2. प्राथमिक स्रोत:

- घरेलू सर्वेक्षण: प्रभावित परिवारों से विस्तृत जानकारी एकत्र करने के लिए संरचित प्रश्नावली का उपयोग किया गया।
- फील्ड विज़िट: साइट विज़िट के दौरान किए गए प्रत्यक्ष अवलोकन और साक्षात्कार ने अतिरिक्त संदर्भ और डेटा प्रदान किया।
- फोकस समूह चर्चाएँ (एफ़ज़ीडी): गुणात्मक डेटा एकत्र करने और परियोजना के संभावित प्रभावों के बारे में हितधारकों के बीच चर्चा को सुविधाजनक बनाने के लिए एफ़ज़ीडी आयोजित की गई।

3. अध्ययन उपकरण तैयार करना:

- प्राथमिक हितधारकों से गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों डेटा एकत्र करने के लिए एक संरचित प्रश्नावली विकसित की गई थी। इस प्रश्नावली का पूर्व परीक्षण, परिशोधन और प्रशिक्षित सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा संचालन किया गया।

4. प्राथमिक सर्वेक्षण:

- सर्वेक्षण में घरेलू विशेषताओं, सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल, व्यवसाय, आय और प्रभावित परिवारों पर परियोजना के संभावित प्रभाव पर डेटा एकत्र करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। उत्तरदाताओं की राय और विचारों को जानने के लिए ओपन-एंडेड प्रश्न शामिल किए गए।

5. फोकस समूह चर्चा:

- परियोजना के कथित प्रभावों की पहचान करने और सकारात्मक परिणामों को बढ़ाने और नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए सुझाव एकत्र करने के लिए समुदाय के नेताओं और प्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ एफ़ज़ीडी आयोजित किए गए।

6. डेटा संग्रह और ग्राउंड सत्यापन का पर्यवेक्षण:

- कोर टीम के सदस्यों ने डेटा संग्रह प्रक्रिया का पर्यवेक्षण किया और डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए घरों के नमूने के लिए ग्राउंड सत्यापन किया गया।

2.4 नमूनाकरण पद्धति

एस०आई०ए टीम ने प्रभावित घरों का एक यादृच्छिक सर्वेक्षण किया, जिसमें राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची से 68 घरों (HH) को शामिल किया गया। डेटा संग्रह प्रक्रिया में व्यापक जानकारी एकत्र करने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तकनीकों का इस्तेमाल किया गया।

1. मात्रात्मक तकनीकें:

- प्राथमिक हितधारकों के बीच घरेलू सर्वेक्षण के लिए पूर्व-परीक्षणित संरचित प्रश्नावली का उपयोग किया गया।

2. गुणात्मक तकनीकें:

- गुणात्मक तकनीकों में सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए), आजीविका विश्लेषण, वरीयता रैंकिंग, फोकस समूह चर्चा (एफजीडी) और सार्वजनिक परामर्श शामिल थे।

2.5 प्रयुक्त सूचना और डेटा स्रोतों का अवलोकन

एस०आई०ए और सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एस० आई० एम० पी०) को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डेटा और सांख्यिकी के आधार पर तैयार किया गया था, जिसमें फील्ड विजिट, हितधारक परामर्श और मौजूदा दस्तावेज जैसे कि आरटीएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 और एचपी आरटीएफसीटीएलएआरआर नियम, 2015 शामिल हैं। आवश्यक जानकारी एकत्र करने के लिए निम्नलिखित डेटा स्रोतों का उपयोग किया गया:

1. सरकारी रिपोर्ट और साहित्य:

- आधिकारिक दस्तावेजों और रिपोर्टों ने जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक जानकारी सहित द्वितीयक डेटा का खजाना प्रदान किया।

2. फील्ड सर्वेक्षण और साइट विजिट:

- प्राथमिक डेटा प्रभावित परिवारों और अन्य हितधारकों के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से एकत्र किया गया था, जो स्थानीय संदर्भ और परियोजना के विशिष्ट प्रभावों के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है।

3. हितधारक परामर्श:

- एफजीडी , सार्वजनिक परामर्श और साक्षात्कार के माध्यम से एकत्रित हितधारकों से इनपुट, एस०आई०ए और एस० आई० एम० पी० को आकार देने में महत्वपूर्ण था।

सर्वेक्षण के दौरान ली गई कुछ तस्वीरें



3. भूमि मूल्यांकन

यह अध्याय शिमला शहर में एमडीआर-66 और एमडीआर-67 पर सड़क विकास, रखरखाव और चौड़ीकरण परियोजना के लिए अधिग्रहित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है। विश्लेषण में भूमि की प्रकृति, वर्तमान उपयोग और वर्गीकरण का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण सहित उपलब्ध मानचित्रों, भूमि सूची और प्राथमिक डेटा स्रोतों का उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त, अध्याय पिछले तीन वर्षों में स्वामित्व पैटर्न, भूमि हस्तांतरण और भूमि उपयोग के रुझानों की जांच करता है।

3.1 भूमि सूची और प्राथमिक स्रोतों से जानकारी

नीचे दी गई तालिका शिमला शहर में एमडीआर-66 और एमडीआर-67 के सुधार और चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तृत विवरण प्रदान करती है, जिसमें विभिन्न परियोजना गतिविधियों के लिए इच्छित उपयोग पर प्रकाश डाला गया है:

तालिका 3-1 शिमला में परियोजना एमडी आर66और 67 के लिए अधिग्रहीत की जाने वाली कुल भूमि और खसरा संख्या

क्रम०	जिले का नाम	तहसील का नाम	गांव/मोहाल/उप-मोहाल	कुल किता	क्षेत्रफल वर्ग मीटर
1	शिमला	शिमला (U)	उप-मोहाल चौड़ा मैदान	15	2133-62
2			कृष्णा नगर	94	3368-70
3			बाजार वार्ड छोटा शिमला	30 (Salam 15 batta 15)	477-50
4			उप-मोहाल बेम्लोई	3	455-58
5			उप-मोहाल छोटा शिमला खास	9	303-11
6			मोहाल अपर कैथू	47 (Salam 21 Batta 26)	2585-25
7			उप-मोहाल तारा हॉल	76 (Saalam 51Batta 25)	4775-91
8			उप-मोहाल काली बाड़ी	16	2446-52

9			उप मुहाल वार्ड लक्कड़ बाजार	31 (Salaam 17 Batta 14)	1274-26
10			उप-मोहाल शांकली	24 (Saalam 8 Batta 16)	1720-07
11			मोहाल संजौली चौक	24 (Saalam 14 Batta 9)	495-07
12			उप-मोहाल यूएस क्लब	10	780-84

नीचे दी गई तालिका में हिमाचल प्रदेश के छोटा शिमला में तिब्बती स्कूल के पास पैदल पथ के निर्माण के लिए अधिग्रहित की जाने वाली कुल भूमि का विवरण दिया गया है। यह अधिग्रहण क्षेत्र में पैदल यात्रियों की सुरक्षा और पहुँच को बढ़ाने के लिए आवश्यक है।

तालिका *Error! No text of specified style in document.* -1 शिमला में परियोजना एमडी आर 66 और 67 के लिए अधिग्रहीत की जाने वाली कुल भूमि और खसरा संख्या

क्रम०	जिले का नाम	तहसील का नाम	गांव/मोहाल/उप-मोहाल	कुल किता	क्षेत्रफल वर्ग मीटर
1.	शिमला	शिमला (U)	उप-मोहाल छोटा शिमला	2	12-60

3.2 परियोजना के प्रभाव में आने वाला संपूर्ण क्षेत्र

इस सड़क विकास और चौड़ीकरण परियोजना के प्रभाव में आने वाले प्राथमिक क्षेत्र एमडीआर-66 और एमडीआर-67 के खंड और छोटा शिमला में तिब्बती स्कूल के पास का क्षेत्र हैं। विशेष रूप से, परियोजना का प्रभाव:

1. एमडीआर-66 (टूटी कंडी से संजौली ढली बाईपास जंक्शन वाया छोटा शिमला): यह सड़क खंड शिमला शहर में एक प्रमुख कनेक्टर है, और प्रस्तावित चौड़ीकरण सीधे इस मार्ग के साथ भूमि और संपत्तियों को प्रभावित करेगा। इस क्षेत्र में अधिग्रहण अधिक लेन बनाकर और सड़क बुनियादी ढांचे में सुधार करके यातायात प्रवाह को बढ़ाने पर केंद्रित है।

2. एमडीआर-67 (विक्ट्री सुरंग से संजौली ढली वाया लक्कड़ बाजार जंक्शन): शिमला के मुख्य यातायात गलियारों का हिस्सा बनने वाला एक और महत्वपूर्ण सड़क खंड। यहां चौड़ीकरण और सड़क सुधार से भीड़भाड़ कम होगी और शहर के प्रमुख हिस्सों तक पहुंच में सुधार होगा।
3. तिब्बती स्कूल, छोटा शिमला: तिब्बती स्कूल के आसपास का क्षेत्र पैदल यात्री पथ के निर्माण से प्रभावित होगा। प्रस्तावित पैदल पथ स्कूली बच्चों और स्थानीय निवासियों की सुरक्षा में सुधार करेगा, जिससे सड़क के इस व्यस्त भाग पर पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित होगा।

अधिग्रहण का दायरा:

1. भूमि अधिग्रहण: अधिग्रहण सड़क चौड़ीकरण और पैदल पथ जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि तक सीमित है। इन उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित कुल भूमि 20,882.53 वर्ग मीटर (2.0883 हेक्टेयर) है।
2. कोई अतिरिक्त अधिग्रहण नहीं: उल्लिखित क्षेत्रों के अलावा, इस परियोजना के लिए कोई अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण अपेक्षित नहीं है। एजेंसी ने वर्तमान परियोजना के दायरे से परे अतिरिक्त भूमि की किसी आवश्यकता को अधिसूचित या इंगित नहीं किया है।

3.3 परियोजना के लिए कुल भूमि की आवश्यकता

इस परियोजना के तहत अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित कुल भूमि 20,882.53 वर्ग मीटर या 2.0883 हेक्टेयर है, जिसमें 12 गाँव और 378 खसरा नंबर शामिल हैं। इस भूमि का उपयोग सड़क चौड़ीकरण और आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जाएगा ताकि यातायात का सुचारु प्रवाह और सुरक्षित पैदल यात्री आवागमन सुनिश्चित हो सके।

3.4 क्षेत्र के आस-पास किसी सार्वजनिक, अप्रयुक्त भूमि का वर्तमान उपयोग

यह इस बात पर जोर देता है कि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित साइट के आस-पास के क्षेत्र में कोई सार्वजनिक भूमि उपलब्ध नहीं है। सार्वजनिक भूमि से तात्पर्य सरकारी स्वामित्व वाली

भूमि से है, और यदि ऐसी कोई भूमि अप्रयुक्त होती (किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं की जा रही होती), तो उसे परियोजना के लिए विचार किया जा सकता था। हालाँकि, इस मामले में, ऐसी कोई भूमि उपलब्ध नहीं है।

भूमि अधिग्रहण का उद्देश्य विशेष रूप से एमडीआर 66 और 67 को चौड़ा करना है। परिवहन, सुरक्षा या बुनियादी ढाँचे की माँगों को पूरा करने के लिए इस सड़क का विस्तार करने की आवश्यकता है, और यह विस्तार केवल मौजूदा सड़क पर या उसके आस-पास ही हो सकता है। चूँकि सड़क का एक निश्चित मार्ग है, इसलिए चौड़ीकरण के लिए आवश्यक कोई भी भूमि सीधे इस मार्ग के साथ स्थित होनी चाहिए।

यह देखते हुए कि परियोजना को एमडीआर 66 और 67 के साथ और आस-पास कोई वैकल्पिक सार्वजनिक भूमि उपलब्ध नहीं है, निर्दिष्ट भूमि का अधिग्रहण आवश्यक हो जाता है। यह अन्य सार्वजनिक भूमि पर विचार करने की संभावना को खारिज करता है, भले ही ऐसी भूमि कहीं और मौजूद हो, क्योंकि वे सड़क पर या उसके आस-पास नहीं होंगी।

संक्षेप में, एमडीआर 66 और 67 चौड़ीकरण परियोजना के लिए भूमि की आवश्यकता क्षेत्र में वैकल्पिक सार्वजनिक भूमि की कमी के कारण है, तथा इसके साथ ही यह तथ्य भी है कि भूमि मौजूदा सड़क पर या उसके समीप स्थित होनी चाहिए।

3.5 परियोजना के लिए आवश्यक प्रत्येक भूखंड के लिए पहले से खरीदी गई, हस्तांतरित, पट्टे पर दी गई/अधिग्रहित भूमि और इच्छित उपयोग

यह स्पष्ट है कि इस परियोजना के लिए पहले कोई भूमि खरीदी, हस्तांतरित, पट्टे पर दी गई या अधिग्रहित नहीं की गई है। इसका मतलब यह है कि एमडीआर 66 और 67 के चौड़ीकरण के लिए आवश्यक भूमि के किसी भी हिस्से पर किसी भी पूर्व कानूनी प्रक्रिया, लेनदेन या समझौते का पालन नहीं किया गया है, जो उन्हें परियोजना के लिए नामित करता। अनिवार्य रूप से, इसका मतलब यह है कि सड़क चौड़ीकरण के लिए आवश्यक सभी भूमि को अभी भी उचित कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से अधिग्रहित किया जाना है।

अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित सभी भूखंडों का इच्छित उपयोग केवल सड़क को चौड़ा करना और पैदल पथ का निर्माण करना है। इन भूखंडों के लिए कोई वैकल्पिक या द्वितीयक उपयोग की योजना नहीं बनाई गई है, और उन्हें अधिग्रहित करने का एकमात्र कारण एमडीआर 66 और 67 की चौड़ाई और क्षमता को बढ़ाना है। यह अधिग्रहण प्रक्रिया के पीछे एक केंद्रित और स्पष्ट उद्देश्य को दर्शाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि भूमि का उपयोग केवल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा।

अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित प्रत्येक खसरा या भूखंड इसी एकमात्र उद्देश्य के लिए है। यह इस विचार को और पुष्ट करता है कि पहचाने गए सभी भूखंडों का उपयोग केवल सड़क चौड़ीकरण परियोजना और पैदल पथ के निर्माण के लिए किया जाना है। भूमि के लिए कोई अतिरिक्त या अप्रत्याशित योजना नहीं है, और प्रत्येक भूखंड को विशेष रूप से एमडीआर 66 और 67 के विस्तार के लिए निर्धारित किया गया है।

परियोजना का मुख्य लक्ष्य एमडीआर 66 और 67 का चौड़ीकरण है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका मतलब है कि भूमि का उपयोग नई सड़क बनाने के बजाय पहले से मौजूद सड़क के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। मौजूदा सड़क को चौड़ा करने में आमतौर पर लेन का विस्तार करना या बेहतर यातायात प्रवाह के लिए अतिरिक्त स्थान बनाना शामिल होता है, जो बदले में सुरक्षा को बढ़ा सकता है और बढ़ती परिवहन आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है।

संक्षेप में, बयान में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि परियोजना के लिए आवश्यक भूमि के संबंध में पहले कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अधिग्रहण के लिए पहचाने गए विशिष्ट भूखंड केवल एमडीआर 66 और 67 को चौड़ा करने और पैदल पथ के निर्माण के उद्देश्य से हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि परियोजना अनावश्यक या असंबंधित भूमि उपयोग को शामिल किए बिना बुनियादी ढांचे के विस्तार पर केंद्रित रहे।

3.6 परियोजना के लिए अधिग्रहित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि की मात्रा और स्थान

इस परियोजना के तहत अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित कुल भूमि 20,882.53 वर्ग मीटर या 2.0883 हेक्टेयर है, जिसमें 12 गाँव और 378 खसरा नंबर शामिल हैं।

3.7 भूमि की प्रकृति, वर्तमान उपयोग और वर्गीकरण

इस अधिग्रहण के तहत कुल भूमि में विभिन्न प्रकार के उपयोग शामिल हैं, जिसमें रास्ते, सड़कें, घरों के सामने छोटे बरामदे, सीढ़ियाँ और वन क्षेत्र शामिल हैं। हालाँकि, इसमें आवासीय और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली कई इमारत संरचनाएँ भी शामिल हैं। प्रत्येक खसरा और भूमि उपयोग की पूरी सूची इस रिपोर्ट के अनुलग्नक में दी गई है।

3.8 जोतों का आकार, स्वामित्व पैटर्न

प्रस्तावित अधिग्रहण के तहत कुल भूमि मुख्य रूप से अगली पीढ़ी को पैतृक रूप से दी गई है, और किरायेदारों के पास आवासीय और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए भी भूमि है।

- **पैतृक स्वामित्व:** अधिग्रहण के लिए विचार की जा रही अधिकांश भूमि पीढ़ियों से परिवारों में चली आ रही है।
- **किराएदारों का कब्जा:** पैतृक स्वामित्व के अलावा, ऐसे किराएदार भी हैं जो वर्तमान में इस संपत्ति पर कब्जा करके आवासीय और व्यावसायिक उपयोग के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। ये किराएदार रह रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, और उनके पास कब्जे के कुछ कानूनी या अनौपचारिक अधिकार हैं।
- **दोहरा उपयोग (आवासीय और वाणिज्यिक):** भूमि मिश्रित उपयोग के उद्देश्य से काम करती है। इसका उपयोग आवासीय जीवन (जहाँ लोगों के घर हैं) और व्यावसायिक गतिविधियों (जैसे दुकानें, व्यवसाय या अन्य व्यावसायिक उद्यम) दोनों के लिए किया जा रहा है।

कुल मिलाकर स्थिति यह दर्शाती है कि प्रस्तावित अधिग्रहण उन परिवारों को प्रभावित करेगा जिनके पास भूमि पर लंबे समय से दावे हैं और उन किराएदारों को भी जो इसका उपयोग जीवन और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए करते हैं। इन कारकों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

3.9 भूमि वितरण और अधिग्रहित किए जा रहे आवासीय घरों की संख्या

इस परियोजना के अंतर्गत अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित कुल भूमि 20,882.53 वर्ग मीटर या 2.0883 हेक्टेयर है, जिसमें 12 गांव और 378 खसरा नंबर शामिल हैं। अधिग्रहित किए जाने वाले प्रस्तावित ढांचों का विवरण नीचे दी गई तालिका 3-3 में दिया गया है।

3.10 भूमि की कीमतें तथा स्वामित्व और हस्तांतरण में हाल ही में हुए परिवर्तन

मुआवजे की गणना के लिए भूमि श्रेणी का वर्गीकरण निम्नानुसार है:

1. श्रेणी-I (0-25 मीटर): संपत्ति/भूमि जिसमें संबंधित खसरा संख्या या उसके भाग का कोई भी बिंदु सड़क से 25 मीटर की दूरी तक भूमि है।
2. श्रेणी-II (20% < आधार दर) (25-50 मीटर): संपत्ति/भूमि जिसमें संबंधित खसरा संख्या या उसके भाग का कोई भी बिंदु ऐसी सड़क से 25 से 50 मीटर की दूरी पर नहीं है।
3. श्रेणी-III (40% < आधार दर) (50-100 मीटर): संपत्ति/भूमि जिसमें संबंधित खसरा संख्या या उसके भाग का कोई भी बिंदु ऐसी सड़क से 50 से 100 मीटर की दूरी पर नहीं है।
4. श्रेणी-IV (50% < आधार दर) (100-1000 मीटर): संपत्ति/भूमि जिसमें संबंधित खसरा संख्या या उसके किसी भाग का कोई भी बिंदु ऐसी सड़क से 100 से 1000 मीटर की दूरी पर नहीं है।
5. श्रेणी-V (60% < आधार दर) (>1000 मीटर): संपत्ति/भूमि जिसमें संबंधित खसरा संख्या या उसके किसी भाग का कोई भी बिंदु ऐसी सड़क से 1000 मीटर या उससे अधिक की दूरी पर नहीं है।

मालिक सर्किल दरों के बजाय वर्तमान बाजार दरों की मांग करते हैं क्योंकि उन्होंने आधिकारिक भूमि मूल्यांकन और वास्तविक बाजार स्थितियों के बीच विसंगति को उजागर किया है।

1. हाल ही में भूमि बिक्री पंजीकरण का अभाव: पिछले कुछ वर्षों में, इस क्षेत्र में भूमि की बिक्री या हस्तांतरण से जुड़े औपचारिक लेन-देन को ठीक से नहीं किया गया/पंजीकृत या प्रलेखित नहीं किया गया है। इस प्रकार सर्किल दरें प्रचलित बाजार दरों से बहुत कम हैं।
2. मालिकों की मांगें: भूमि मालिक, अपनी संपत्तियों के वास्तविक बाजार मूल्य से अवगत हैं, आधिकारिक सर्किल दर के बजाय वर्तमान बाजार दर के आधार पर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि सर्किल दर पर मुआवजा दिए जाने से उनकी भूमि का मूल्य कम होगा और परिणामस्वरूप अनुचित मुआवजा मिलेगा, क्योंकि आधिकारिक

दर आज के बाजार में भूमि के वास्तविक मूल्य को नहीं दर्शाती है। पिछले तीन वर्षों की अवधि में एस०आई०ए टीम को स्वामित्व में कोई बदलाव नहीं मिला।

तालिका 3-3 शिमला, हिमाचल प्रदेश में परियोजना एमडीआर 66 और 67 के तहत भूमि अधिग्रहण से प्रभावित आवासीय और वाणिज्यिक संरचनाओं का अवलोकन

मोहाल/उप-मोहाल	खसरा प्रविष्टि की संख्या	भूमि उपयोग का प्रकार
तारा हाल	9	आवासीय और व्यावसायिक भवन
कृष्णा नगर	27	आवासीय, व्यावसायिक भवन और शौचालय
बाजार वार्ड छोटा शिमला	15	आवासीय, व्यावसायिक भवन और शौचालय
बाजार वार्ड छोटा शिमला	2	आवासीय, व्यावसायिक भवन
मोहाल अपर कैथू	8	आवासीय, व्यावसायिक भवन
उप-मोहाल काली बाड़ी	4	आवासीय और शौचालय
उप मुहाल वार्ड लक्कड़ बाजार	5	आवासीय, व्यावसायिक भवन और शौचालय
उप-मोहाल शांकली	1	आवासीय
मोहाल संजौली चौक	13	आवासीय, व्यावसायिक भवन
उप-मोहाल यूएस क्लब	1	पहरा घर

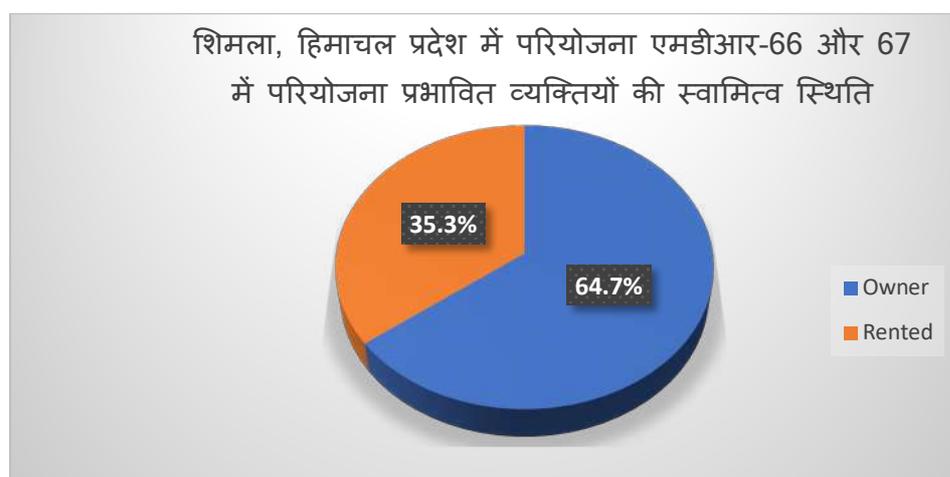
4. प्रभावित परिवारों और संपत्तियों का आकलन और गणना

यह अध्याय सड़क चौड़ीकरण और विकास परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों और व्यक्तियों का आकलन और गणना प्रदान करता है। यह प्रभावित क्षेत्रों में निजी और आम संपत्तियों के साथ-साथ सार्वजनिक भूमि उपयोग निर्भरताओं पर पड़ने वाले प्रभाव को रेखांकित करता है। अध्याय में स्थानीय समुदायों पर भूमि अधिग्रहण के प्रभाव की सीमा का भी विवरण दिया गया है, जो एक व्यापक प्राथमिक सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा से लिया गया है। विश्लेषण का उद्देश्य अधिग्रहण से उत्पन्न होने वाले सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों को उजागर करना है, जिससे प्रभावित आबादी की स्पष्ट तस्वीर सामने आती है।

4.1 सीधे प्रभावित व्यक्ति

4.1.1. किराएदार/कब्जाधारी

शिमला राज्य का सबसे बड़ा शहर है, और यहाँ के कई निवासी किराए के मकानों में रहते हैं। अधिग्रहण से प्रभावित कई इमारतों में किराएदार भी रहते हैं, जो इस प्रक्रिया से प्रभावित होंगे। नीचे दिए गए चित्र में विवरण दिया गया है:



आकृति 4-1 शिमला, हिमाचल प्रदेश में परियोजना एमडीआर 66 और 67 में परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की स्वामित्व स्थिति

4.1.2. साझा संपत्ति संसाधनों (सीपीआर) पर निर्भरता

सर्वेक्षण के दौरान, अधिग्रहित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर कोई सीपीआर नहीं पाया गया।

4.1.3. आजीविका के लिए भूमि पर निर्भरता

अधिकांश प्राथमिक हितधारक और किरायेदार अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित संपत्तियों पर निर्भर हैं, जिनका उपयोग हितधारकों द्वारा वाणिज्यिक गतिविधियों और आजीविका कमाने के लिए किया जा रहा है।

5. सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक प्रोफाइल

यह अध्याय परियोजना क्षेत्र में प्रभावित समुदायों की सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषताओं का गहन विश्लेषण प्रदान करता है। यहाँ प्रस्तुत जानकारी प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाली आबादी की जनसांख्यिकीय संरचना, आय स्रोत, व्यावसायिक पैटर्न, शिक्षा स्तर और सांस्कृतिक प्रथाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, अध्याय सामुदायिक बुनियादी ढाँचे, सामाजिक नेटवर्क और सांस्कृतिक विरासत की जाँच करता है, जो एक साथ सामाजिक गतिशीलता और आजीविका का व्यापक अवलोकन प्रदान करते हैं। प्राथमिक सर्वेक्षणों, फोकस समूह चर्चाओं और द्वितीयक स्रोतों के संयोजन के माध्यम से डेटा एकत्र किया गया था, जिससे आबादी और इसकी संभावित कमज़ोरियों की समग्र समझ सुनिश्चित हुई।

5.1 परियोजना क्षेत्र में परियोजना से प्रभावित लोगों की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल

एस०आई०ए के हिस्से के रूप में, टीम ने प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के संभावित सामाजिक और आर्थिक प्रभावों पर डेटा एकत्र करने के लिए कुल 68 परिवारों को शामिल करते हुए एक यादृच्छिक सर्वेक्षण किया। प्राथमिक सर्वेक्षण का उद्देश्य स्थानीय आबादी पर विचारों, चिंताओं और समग्र प्रभाव को जानना था।

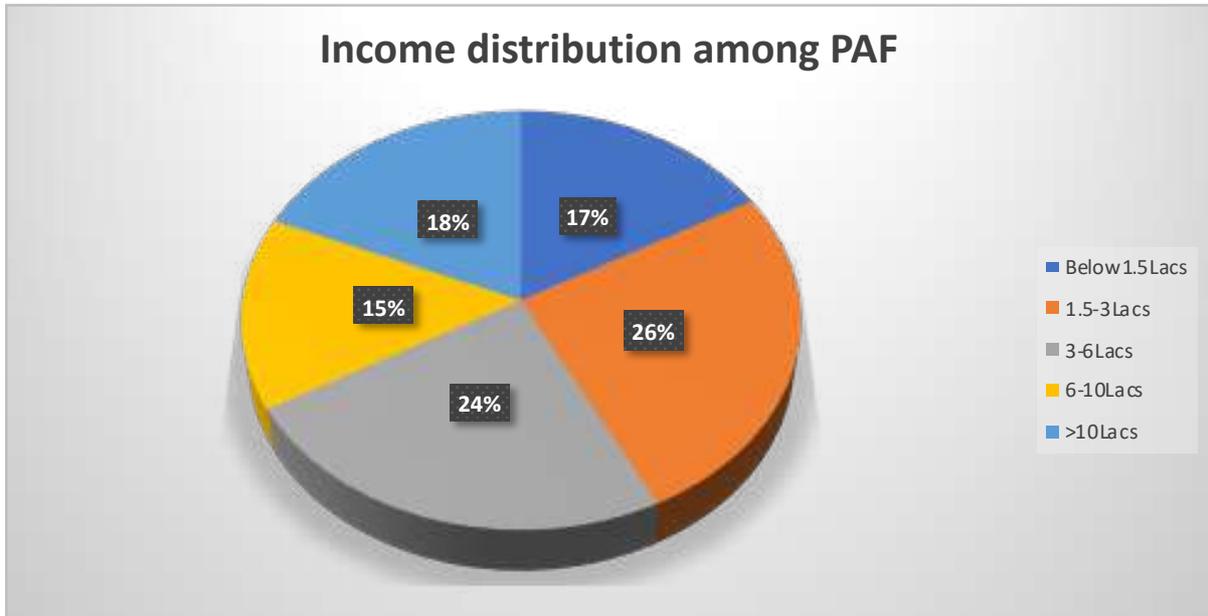
तालिका 5-1 परियोजना से सीधे प्रभावित लोगों की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल

मोहाल/उप मोहाल	पुरुष	महिला	बच्चे (0-5)	कुल	परिवारों की संख्या
संजौली चौक	15	14	2	29	6
छोटा शिमला	19	18	1	37	12
चौरा मैदान	6	8	0	14	6
अपर कैथू	7	13	0	22	3
तारा हॉल	12	20	0	32	6
शंकलिन	14	0	0	14	2

लक्कड़ बाजार	5	12	0	17	3
कृष्णा नगर	86	81	7	167	30
कुल	164	176	10	350	68

5.2 आय और गरीबी का स्तर

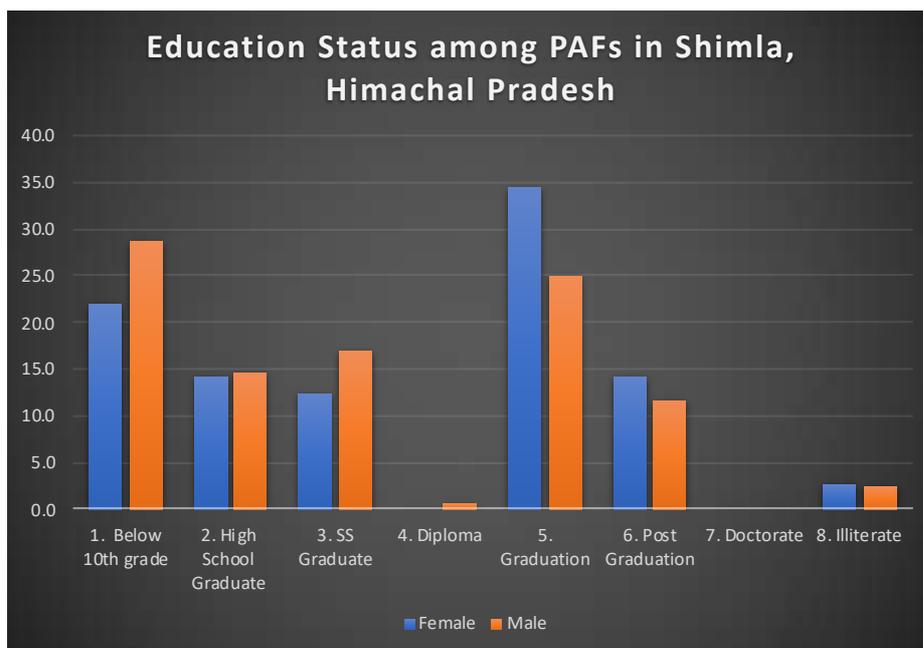
प्रभावित परिवारों के बीच किए गए सर्वेक्षण में, आय वितरण से पता चला कि लगभग 50% आबादी ₹1.5 लाख से ₹6 लाख की वार्षिक आय सीमा के भीतर रहती है। इसके अतिरिक्त, 15% परिवार ₹6 लाख से ₹10 लाख की सीमा में आते हैं, जबकि 18% की वार्षिक आय ₹10 लाख से अधिक है। उल्लेखनीय रूप से, 17% परिवारों को ₹1.5 लाख की वार्षिक आय सीमा से नीचे रहने वाले के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह जनसांख्यिकीय विश्लेषण इंगित करता है कि कम आय वाले परिवारों को अधिग्रहण के परिणामस्वरूप अधिक स्पष्ट प्रतिकूल प्रभावों का अनुभव होने की संभावना है, जो इन कमजोर आबादी का समर्थन करने के लिए लक्षित शमन रणनीतियों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।



आकृति 5-1 प्रभावित परिवारों का आय वितरण

5.3 परियोजना प्रभावित परिवारों की साक्षरता स्थिति

सर्वेक्षण के निष्कर्ष शिमला में परियोजना प्रभावित परिवारों के बीच पुरुष और महिला के मध्य में शैक्षिक प्राप्ति में महत्वपूर्ण असमानता दर्शाते हैं। पुरुष और महिला, अधिकांश ने कम से कम हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की है, हालाँकि व्यक्तियों का एक उल्लेखनीय प्रतिशत, विशेष रूप से पुरुषों में, शिक्षा का निम्न स्तर है। 75% महिलाओं ने हाई स्कूल से विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा पूरी करने की सूचना दी, जबकि 69% पुरुष परियोजना प्रबंधकों ने यह सूचना दी। इसके अलावा, 25% महिलाओं ने हाई स्कूल से नीचे की कुछ शिक्षा प्राप्त करने या निरक्षर होने का संकेत दिया, जबकि 31% पुरुष इस श्रेणी में आते हैं। इससे पता चलता है कि पुरुष अनुपात में उनकी महिला समकक्षों की तुलना में सीमित औपचारिक शिक्षा है। शैक्षिक श्रेणियों के विभाजन से पता चलता है कि पुरुषों में हाई स्कूल से नीचे, हाई स्कूल स्नातक और डिप्लोमा योग्यता वाले व्यक्तियों का प्रतिशत अधिक है। हालांकि, स्नातकोत्तर शिक्षा के मामले में महिला पुरुषों से आगे हैं। इससे पता चलता है कि पुरुष पीएफ की समग्र शैक्षिक उपलब्धि भले ही अधिक हो, लेकिन महिला पीएफ के उच्चतर अध्ययन करने की संभावना अधिक है। चित्र 5.2 इन निष्कर्षों का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, जो शिमला में पीएफ के बीच शैक्षिक स्थिति में असमानताओं को और अधिक उजागर करता है।



आकृति 5-2 शिमला, हिमाचल प्रदेश में परियोजना प्रभावित परिवारों के बीच शिक्षा की स्थिति (%)

5.4 कमज़ोर समूह

किराएदार और कुछ ज़मीन मालिक संबंधित संपत्तियों पर छोटे-छोटे व्यवसाय चला रहे हैं। ये व्यवसाय अनौपचारिक या सूक्ष्म उद्यम हैं, जैसे स्थानीय दुकानें, छोटे खुदरा आउटलेट, खाद्य स्टॉल या अन्य सेवा-उन्मुख उद्यम जो तत्काल समुदाय की सेवा करते हैं। इन व्यवसायों से उत्पन्न आय न्यूनतम है, जिसका अर्थ है कि ये व्यक्ति केवल बुनियादी जीवन व्यय को कवर करने के लिए ही कमा रहे हैं। ये छोटे व्यवसाय शामिल परिवारों के लिए आय का प्राथमिक या एकमात्र स्रोत हैं। इन व्यवसायों को संचालित करने वाले व्यक्ति अपने और अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए पूरी तरह से दैनिक आय पर निर्भर होने की संभावना रखते हैं। उनके व्यवसाय में किसी भी व्यवधान का उनकी आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।

पर्याप्त मुआवज़ा या सहायता के बिना, ये परिवार आजीविका के नए साधन खोजने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। इसका प्रभाव दीर्घकालिक हो सकता है, क्योंकि उन्हें अपने व्यवसाय को कहीं और फिर से बनाने में या सीमित कौशल या वित्तीय संसाधनों के कारण वैकल्पिक रोजगार हासिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यह स्थिति आर्थिक कमज़ोरी को बढ़ा सकती है, जिससे ये परिवार गरीबी में जा सकते हैं।

5.5 रिश्तेदारी पैटर्न

हिमाचल प्रदेश में, भूमि अधिकार केवल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किए जाते हैं। राज्य के नियमों के अनुसार, प्रवासियों को हिमाचल प्रदेश में ज़मीन खरीदने की अनुमति नहीं है। नतीजतन, इस क्षेत्र में ज़मीन आम तौर पर पैतृक संपत्ति होती है और वसीयत द्वारा निर्दिष्ट न किए जाने तक कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच समान रूप से वितरित की जाती है। महिलाएँ पारिवारिक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और ज़्यादातर घरेलू काम महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। हालाँकि, इन कार्यों के आर्थिक मूल्य को आम तौर पर मान्यता नहीं दी जाती है या उनका हिसाब नहीं रखा जाता है।

शिमला शहर में, कई ऐसी संपत्तियों की मौजूदगी के कारण स्थिति और भी जटिल हो जाती है जो स्वतंत्रता-पूर्व युग की हैं। कई व्यक्तियों ने इन संपत्तियों पर कब्ज़ा कर लिया है और उन

पर अपना अधिकार जताया है, जिसके परिणामस्वरूप जटिल संपत्ति अधिकार मामले सामने आए हैं। यह ऐतिहासिक संदर्भ शिमला में संपत्ति के स्वामित्व और दावों में जटिलता की परतें जोड़ता है।

5.6 प्रशासनिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और नागरिक समाज संगठन

शिमला हिमाचल प्रदेश राज्य की राजधानी है। इसलिए, सभी प्रमुख प्रशासनिक प्रभाग और राजनीतिक संगठन, सांस्कृतिक और नागरिक समाज संगठन किसी भी विकासात्मक/सरकारी नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए एमडीआर-66 और एमडीआर-67 के चौड़ीकरण और विकास जैसी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया और सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) में भागीदारी प्रमुख हो जाती है।

प्रशासनिक ढांचा

शिमला में प्रशासन मुख्य रूप से शिमला नगर निगम द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जो शहर की शहरी नियोजन, भूमि उपयोग और बुनियादी ढांचे के विकास की देखरेख करता है। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग और शहरी विकास विभाग जैसे विभिन्न राज्य स्तरीय सरकारी निकाय भी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

नगरपालिका प्रशासन का नेतृत्व निर्वाचित नगर पार्षदों द्वारा किया जाता है, जो शिमला में विभिन्न वार्डों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नगर निगम का प्रशासनिक प्रमुख आयुक्त होता है, जो नीतियों के दैनिक संचालन और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार राज्य द्वारा नियुक्त अधिकारी होता है। आयुक्त की भूमिका यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है कि राज्य की नीतियाँ स्थानीय शासन के साथ संरेखित हों और कुशलतापूर्वक क्रियान्वित हों। हिमाचल प्रदेश की राजधानी के रूप में, शिमला राज्य की राजनीतिक गतिविधियों के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करता है, जहाँ सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के कार्यालय हैं।

सांस्कृतिक विचार

अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ शिमला न केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण शहर है। यह शहर कई विरासत संरचनाओं का घर है जो इसके औपनिवेशिक अतीत को दर्शाती हैं, साथ ही धार्मिक स्थल भी हैं जो इसकी विविध आबादी की आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। शिमला में कई प्रमुख हिंदू मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद और एक बुद्ध मठ हैं, जो इसे धार्मिक और सांस्कृतिक संगम का केंद्र बनाते हैं।

शहर में और उसके आसपास स्थित ये सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल, इसके निवासियों और आगंतुकों के जीवन में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं, जो परंपरा, आध्यात्मिकता और इतिहास के केंद्र के रूप में शिमला की पहचान में योगदान करते हैं।

नागरिक समाज संगठन

राज्य के प्रशासन का केंद्र होने के नाते, शिमला में कई नागरिक समाज संगठन (सीएसओ) और गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) सक्रिय हैं, जो सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण और प्रभावित आबादी के अधिकारों की वकालत करते हैं। ये संगठन एस०आई०ए के संचालन की पारदर्शिता और जवाबदेही में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

ये प्रशासनिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और नागरिक समाज संस्थाएँ सामूहिक रूप से एस०आई०ए के पारदर्शी और समावेशी निष्पादन में योगदान देती हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि सड़कों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे का विकास सामाजिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक चिंताओं के साथ संतुलित हो।

5.7 क्षेत्रीय गतिशीलता और ऐतिहासिक परिवर्तन प्रक्रियाएँ

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में समय के साथ महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और ऐतिहासिक परिवर्तन हुए हैं। इसके विकास और गतिशीलता पर विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ताकतों का प्रभाव रहा है। प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण शिमला शहर के लगभग मुख्य क्षेत्र में है और कई होटल, व्यापारिक संस्थाएँ और छोटी दुकानें सड़कों के किनारे स्थित हैं।

1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद, शिमला ने ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में अपनी प्रमुखता खो दी। हालाँकि, 1971 में हिमाचल प्रदेश की राजधानी के रूप में इसकी स्थिति ने

इसे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में बनाए रखा। स्वतंत्रता के बाद, शहर ने बढ़ती आबादी और सरकारी कार्यों को समायोजित करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे का विस्तार करना शुरू कर दिया। स्वतंत्रता के बाद शिमला के विस्तार ने तेजी से शहरीकरण देखा। बढ़ती आबादी ने आवासीय कॉलोनियों और वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास को जन्म दिया। हालाँकि, पहाड़ी इलाकों ने विस्तार को सीमित कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्रों में उच्च जनसंख्या घनत्व और भूमि और संसाधनों पर दबाव पड़ा। शिमला की आबादी लगातार बढ़ी है, जिसमें लोग नौकरी और बेहतर रहने की स्थिति की तलाश में ग्रामीण हिमाचल और भारत के अन्य हिस्सों से पलायन कर रहे हैं। इस आमद ने शहर में विभिन्न भाषाई और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों के बसने के साथ एक विविध जनसांख्यिकी में योगदान दिया है।

आधुनिकीकरण के बावजूद, शिमला ने अपने औपनिवेशिक आकर्षण को बरकरार रखा है, जिसमें विभिन्न इमारतों और संरचनाओं ने ब्रिटिश युग की विरासत को संरक्षित किया है। हालाँकि, हिमाचल प्रदेश की स्थानीय संस्कृति, जिसमें इसके त्यौहार, भोजन और पारंपरिक प्रथाएँ शामिल हैं, शहर में एक मजबूत प्रभाव बनी हुई हैं। पिछले कुछ वर्षों में, शिमला ने पारंपरिक हिमाचली रीति-रिवाजों को आधुनिक शहरी जीवन शैली के साथ मिश्रित होते देखा है।

बुनियादी ढाँचे की चुनौतियाँ

शिमला को यातायात की भीड़, अधिक जनसंख्या और अपर्याप्त जल आपूर्ति जैसी आधुनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, खासकर गर्मियों के महीनों के दौरान जब पर्यटन चरम पर होता है। स्थानीय अधिकारियों द्वारा बुनियादी ढाँचे में सुधार करने के प्रयास किए गए हैं, जैसे कि पार्किंग स्थल विकसित करना, जल प्रबंधन प्रणाली और सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को उन्नत करना। विकास और संरक्षण को संतुलित करना: आधुनिक विकास को पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। शिमला के जंगलों को संरक्षित करने, कचरे का प्रबंधन करने और इसके प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने की पहल की जा रही है, क्योंकि शहर की पर्यावरणीय स्थिरता इसकी दीर्घकालिक व्यवहार्यता के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर एक पर्यटन स्थल के रूप में।

5.8 रहने के माहौल की गुणवत्ता

शिमला भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित एक खूबसूरत शहर है। यह समुद्र तल से 2,146 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है और हरे-भरे जंगलों और बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है। यह शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है, जो इसे एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाता है।

रहने के माहौल की गुणवत्ता के संदर्भ में, शिमला में ठंडी गर्मियों और ठंडी सर्दियों के साथ एक सुखद जलवायु है। हवा की गुणवत्ता आम तौर पर अच्छी है, प्रदूषण का स्तर कम है, और पानी की गुणवत्ता भी सुरक्षित और साफ मानी जाती है। शहर अपेक्षाकृत ध्वनि प्रदूषण से मुक्त है, जो इसके शांतिपूर्ण वातावरण में इजाफा करता है।

शिमला में एक अच्छी तरह से नियोजित और अच्छी तरह से बनाए रखा बुनियादी ढांचा है, जिसमें अच्छी तरह से पक्की सड़कें, पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन और विश्वसनीय बिजली और पानी की आपूर्ति है। शहर में अच्छी चिकित्सा सुविधाएँ और शैक्षणिक संस्थान भी हैं, जो इसे परिवारों और बच्चों के रहने के लिए उपयुक्त स्थान बनाते हैं।

कुल मिलाकर, शिमला अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांतिपूर्ण वातावरण और अच्छी तरह से विकसित बुनियादी ढांचे के साथ रहने के माहौल की उच्च गुणवत्ता प्रदान करता है। शहरीकरण में वृद्धि के साथ, पर्यावरणीय चुनौतियाँ, वनों की कटाई, पानी की कमी, भूस्खलन, अपशिष्ट प्रबंधन और यातायात की भीड़ और ट्रैफिक जाम प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान छोटी आबादी के लिए डिज़ाइन किया गया शहर का बुनियादी ढांचा आधुनिक विकास की माँगों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है, जिससे नागरिक सुविधाओं पर दबाव पड़ता है।

6. सामाजिक प्रभाव

यह अध्याय शिमला में एमडीआर -66 और एमडीआर -67 पर सड़क चौड़ीकरण और विकास परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के प्रत्याशित सामाजिक प्रभावों की जांच करता है। यह परियोजना से प्रभावित परिवारों, समुदायों और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर होने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिणामों का आकलन करता है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभावों का विश्लेषण किया जाता है, जिसमें आजीविका, रोजगार, आय, संसाधनों तक पहुंच, सामाजिक सामंजस्य और सांस्कृतिक प्रथाओं जैसे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। महिलाओं के नेतृत्व वाले परिवार, बुजुर्ग और आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों जैसे कमजोर समूहों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिन्हें अधिक गंभीर प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। प्रस्तुत निष्कर्ष घरेलू सर्वेक्षणों, हितधारक परामर्शों और फोकस समूह चर्चाओं से एकत्र किए गए डेटा पर आधारित हैं, जो इस बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं कि परियोजना क्षेत्र के सामाजिक ताने-बाने को कैसे नया रूप देगी।

6.1 प्रभावों की पहचान करने के लिए रूपरेखा और दृष्टिकोण

परियोजना का एस०आई०ए एमडीआर-66 और एमडीआर-67 पर सड़क विकास, चौड़ीकरण और रखरखाव और तिब्बती स्कूल छोटा शिमला के पास पैदल पथ का निर्माण भूमि अधिग्रहण के कारण उत्पन्न होने वाले संभावित सामाजिक नतीजों का आकलन करने के लिए किया गया था। एस०आई०ए का उद्देश्य स्थानीय आबादी, समुदायों और सांस्कृतिक प्रणालियों पर परियोजना के संभावित प्रभावों की पहचान करना है। निर्णय लेने के उपकरण के रूप में, एस०आई०ए परियोजना योजनाकारों को सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एसआईएमपी) के माध्यम से नकारात्मक प्रभावों का अनुमान लगाने और उन्हें कम करने में मदद करता है।

सामाजिक प्रभावों की पहचान करने के लिए रूपरेखा और दृष्टिकोण ने सभी हितधारकों को शामिल करते हुए एक व्यवस्थित प्रक्रिया का पालन किया। इस प्रक्रिया में मुख्य चरण हैं:

- चरण 1: समान परियोजनाओं के सामाजिक संदर्भ को समझने के लिए पृष्ठभूमि अध्ययन और केस स्टडीज की समीक्षा।
- चरण 2: परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) और प्रभावित होने वाले समूहों की पहचान।

- चरण 3: प्रभावित परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को पकड़ने के लिए तैयार एक प्राथमिक सर्वेक्षण प्रश्नावली का विकास।
- चरण 4: गहन जानकारी एकत्र करने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ प्राथमिक सर्वेक्षण और फोकस समूह चर्चा (एफजीडी) आयोजित करना।
- चरण 5: पैटर्न और अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए सर्वेक्षणों और चर्चाओं से एकत्र किए गए डेटा का विश्लेषण।
- चरण 6: विभिन्न सामाजिक प्रभावों की पहचान करना, उनकी तीव्रता का निर्धारण करना और उन्हें विशिष्ट परियोजना क्षेत्रों में मैप करना।

यह व्यवस्थित दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि विश्लेषण परियोजना के सभी संभावित सामाजिक परिणामों, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों को व्यापक रूप से संबोधित करता है।

6.2 6.2 परियोजना के विभिन्न चरणों में प्रभावों का विवरण

शिमला में एमडीआर-66 और एमडीआर-67 के साथ सड़क विकास परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के सामाजिक प्रभावों को तीन प्रमुख चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है: निर्माण-पूर्व, निर्माण और संचालन। इन चरणों में स्थानीय समुदाय के साथ जुड़ाव के विभिन्न स्तर शामिल होंगे और इनके सामाजिक परिणाम अलग-अलग होंगे। पूरी तरह से विस्तृत परियोजना प्रस्ताव या व्यवहार्यता अध्ययन की अनुपस्थिति के कारण, प्रत्येक चरण में संभावित प्रभावों का केवल एक सामान्य मूल्यांकन प्रदान किया जा सकता है। इन्हें नीचे दी गई तालिका में संक्षेपित किया गया है।

सामाजिक प्रभाव के चरण:

1. निर्माण-पूर्व चरण:

- **भूमि अधिग्रहण और विस्थापन:** इस चरण के दौरान, प्राथमिक सामाजिक प्रभाव भूमि और उस पर आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत संपत्तियों सहित किसी भी संरचना के अधिग्रहण के इर्द-गिर्द घूमता है। इससे व्यवसायों का विस्थापन हो सकता है और आजीविका में व्यवधान हो सकता है, खासकर प्रभावित मार्गों के साथ दुकानदारों और छोटे उद्यमों के लिए।
- **सार्वजनिक विरोध:** भूमि अधिग्रहण से प्रभावित निवासियों या व्यवसाय मालिकों की ओर से चिंता या विरोध हो सकता है या उन्हें संपत्ति के मूल्यों में कमी का डर हो सकता है।

- **मुआवज़ा और पुनर्वास:** प्रभावित संपत्ति मालिकों को मुआवज़ा देने और विस्थापित व्यक्तियों या व्यवसायों के पुनर्वास की सुविधा प्रदान करने की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और प्रभावित पक्षों के साथ संचार के साथ सावधानीपूर्वक संभालना होगा।

2. निर्माण चरण:

- **यातायात व्यवधान और सड़क सुरक्षा:** निर्माण के दौरान, स्थानीय यातायात में व्यवधान हो सकता है, जिससे भीड़भाड़ बढ़ सकती है, कुछ क्षेत्रों तक पहुँच कम हो सकती है और अस्थायी रूप से व्यापार पर निर्भर व्यवसायों की आजीविका प्रभावित हो सकती है।
- **शोर, धूल और वायु प्रदूषण:** निर्माण गतिविधियों से शोर, धूल और वायु प्रदूषण उत्पन्न होने की संभावना है, जो आसपास के पर्यावरण और निवासियों के दैनिक जीवन को प्रभावित करेगा। नियंत्रित निर्माण प्रथाओं के माध्यम से इन कारकों को कम करना आवश्यक होगा।
- **रोजगार के अवसर:** निर्माण चरण स्थानीय मजदूरों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए अल्पकालिक रोजगार के अवसर प्रदान कर सकता है। हालाँकि, यह एक क्षणिक प्रभाव है और इसे दैनिक जीवन में संभावित व्यवधानों के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।

3. परिचालन चरण:

- **बेहतर कनेक्टिविटी:** परियोजना पूरी हो जाने के बाद, इसका मुख्य सकारात्मक प्रभाव सड़क अवसंरचना में सुधार, शिमला में प्रमुख स्थानों के बीच कनेक्टिविटी में वृद्धि, जिससे यातायात प्रवाह में सुगमता और यात्रा समय में कमी आएगी।
- **आर्थिक विकास:** बेहतर सड़क अवसंरचना से शिमला में पर्यटन और वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इससे शहर में आवागमन अधिक सुगम हो जाएगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान मिलेगा।
- **अवसंरचना का रखरखाव:** सड़कों और पैदल पथों का निरंतर रखरखाव आवश्यक होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित और प्रभावी बने रहें। रखरखाव की उपेक्षा करने से दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, जिसमें सुरक्षा में कमी और भविष्य में मरम्मत की लागत में वृद्धि शामिल है।

सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एस० आई० एम० पी०) का उद्देश्य तीनों चरणों के दौरान परियोजना से जुड़े सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाते हुए प्रतिकूल प्रभावों को कम करना है। प्रबंधन उपायों के साथ-साथ विभिन्न प्रभावों का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना परियोजना के प्रत्येक चरण के दौरान संभावित सामाजिक प्रभावों को संबोधित करने का प्रयास करती है। उचित योजना और कार्यान्वयन से प्रतिकूल प्रभाव कम हो जाएंगे तथा शिमला क्षेत्र के लिए एमडीआर-66 और एमडीआर-67 सड़क विकास परियोजना के दीर्घकालिक लाभ में वृद्धि होगी।

तालिका 6-1 परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों में सामाजिक प्रभावों का विवरण

परियोजना चरण	सामाजिक प्रभाव	सामाजिक प्रभाव प्रबंधन उपाय
निर्माण-पूर्व	भूमि अधिग्रहण और संपत्तियों का विस्थापन।	उचित मुआवज़ा, प्रभावित पक्षों के साथ पारदर्शी संचार
	भूमि अधिग्रहण के प्रति जनता का विरोध	समुदाय के साथ जुड़ाव, चिंताओं को संबोधित करना, कानूनी ढाँचे
निर्माण	यातायात में व्यवधान, भीड़भाड़ में वृद्धि	यातायात प्रबंधन योजनाएँ, वैकल्पिक मार्ग
	निर्माण गतिविधियों से शोर, धूल और वायु प्रदूषण	शोर और धूल नियंत्रण उपायों का कार्यान्वयन
	स्थानीय लोगों के लिए अस्थायी रोजगार	स्थानीय श्रम और आपूर्तिकर्ताओं को काम पर रखने को प्राथमिकता दें
संचालन	सड़क संपर्क और यातायात प्रवाह में वृद्धि	बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित रखरखाव
	पर्यटन और वाणिज्य में वृद्धि के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा	आर्थिक प्रभावों की निगरानी करें और सामुदायिक लाभ सुनिश्चित करें
	बुनियादी ढांचे के रखरखाव और रख-रखाव की दीर्घकालिक आवश्यकता	गिरावट को रोकने के लिए स्थायी रखरखाव रणनीतियाँ विकसित करें

6.3 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों द्वारा अनुभव किए गए प्रभाव

प्रभावित हितधारकों के साथ परामर्श पुनर्वास और पुनर्स्थापन से संबंधित अनैच्छिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए शुरुआती बिंदु था। इस परियोजना से प्रभावित लोगों को कई दशकों से अपना व्यवसाय खोने और इस प्रकार प्रमुख भूमि और संपत्तियों के नुकसान के अलावा आजीविका के अवसरों को खोने की आशंका है।

प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान, केवल कुछ उत्तरदाताओं ने साझा किया कि उक्त परियोजना के कारण कुछ सकारात्मक प्रभाव होंगे, जिसमें शहर में यातायात का सुचारु प्रवाह शामिल है। उनमें से कुछ को उम्मीद है कि बेहतर सड़क नेटवर्क के कारण वाहनों की औसत गति में वृद्धि होगी और परिवहन सेवाओं की आवृत्ति में वृद्धि होगी।

अधिकांश उत्तरदाता नकारात्मक प्रभावों के बारे में चिंतित थे। इनमें से मुख्य प्रमुख भूमि और व्यवसाय का नुकसान था जो उनकी आजीविका, जीवन शैली और सामाजिक संबंधों पर बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा।

6.4 एमडीआर परियोजना के बारे में जागरूकता

प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान, औसतन 50% उत्तरदाताओं ने कहा कि वे आगामी परियोजना के बारे में आंशिक रूप से जानते थे। 30% ने कहा कि वे पूरी तरह से अवगत हैं और 20% ने बताया कि वे परियोजना, इसके उद्देश्य और पात्र मुआवजे के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं।

6.5 परियोजना के लिए सहमति

सर्वेक्षण के दौरान, 93% लोगों ने कहा कि उन्हें प्रस्तावित अधिग्रहण पर आपत्ति है, दूसरी ओर 5% ने भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की और शेष 2% इसके बारे में निश्चित नहीं थे।

6.6 मुआवजे की प्राथमिकताएँ

सर्वेक्षण के दौरान अधिकांश पीएपी ने अपने व्यवसाय की स्थापना के लिए प्राथमिक स्थान पर भूमि और प्रचलित बाजार दरों पर नकद मुआवजे की मांग की।

7. लागत और लाभ का विश्लेषण तथा अधिग्रहण पर सिफारिशें

यह अध्याय सार्वजनिक उद्देश्य के आकलन, कम विस्थापन का कारण बनने वाले विकल्प, परियोजना के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि और प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण की समग्र व्यवहार्यता के बारे में अंतिम निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। इसमें प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में शमन उपायों और उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन भी शामिल है।

विश्लेषण में अधिग्रहण से उत्पन्न होने वाले सामाजिक प्रभावों की प्रकृति और तीव्रता को शामिल किया गया है, जो परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी), और आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। इसका उद्देश्य यह आकलन करना है कि प्रस्तावित परियोजना के लाभ हितधारकों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों से अधिक हैं या नहीं।

इसमें विस्थापन, आजीविका के नुकसान और भूमि उपयोग पैटर्न में बदलाव सहित सामाजिक और आर्थिक लागतों के मुकाबले बेहतर बुनियादी ढांचे, बेहतर परिवहन और संभावित आर्थिक विकास जैसे संभावित समग्र लाभों के बीच तुलना की गई है। अध्याय में यह भी जांच की गई है कि क्या परियोजना सार्वजनिक हित में है और शमन उपाय किस तरह से कुछ सबसे गंभीर प्रभावों को कम कर सकते हैं।

लागत, लाभ और शमन संभावनाओं के इस व्यापक मूल्यांकन के आधार पर, अध्याय इस बात पर अंतिम अनुशंसा प्रदान करता है कि भूमि अधिग्रहण को आगे बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं, जबकि प्रभावित लोगों के लिए उचित मुआवजा और उचित व्यवहार सुनिश्चित करते हुए व्यापक सार्वजनिक हित को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

7.1 सार्वजनिक उद्देश्य का मूल्यांकन

शिमला में एमडीआर 66 और एमडीआर 67 को चौड़ा करने के लिए भूमि अधिग्रहण कई प्रमुख सार्वजनिक उद्देश्यों को पूरा करता है जो समुदाय के लिए फायदेमंद हैं:

1. बेहतर सड़क अवसंरचना: इन प्रमुख जिला सड़कों के चौड़ीकरण से सड़क क्षमता में वृद्धि होगी, यातायात का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित होगा, भीड़भाड़ कम होगी और समग्र परिवहन नेटवर्क में सुधार होगा।
2. बेहतर कनेक्टिविटी: इन सड़कों के विस्तार से शिमला और पड़ोसी क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी में काफी सुधार होगा, जिससे निवासियों, पर्यटकों और व्यवसायों के लिए आसान पहुँच होगी।
3. आर्थिक विकास: बेहतर सड़क अवसंरचना अधिक वाणिज्यिक गतिविधियों, पर्यटन और व्यापार को आकर्षित करेगी, जो शिमला और आसपास के क्षेत्रों के आर्थिक विकास में योगदान देगी। इससे यात्रा का समय भी कम होगा और उत्पादकता बढ़ेगी।
4. सार्वजनिक सुरक्षा: चौड़ी सड़कें बेहतर लेन पृथक्करण, सुरक्षित पैदल पथ और बेहतर सड़क की स्थिति प्रदान करके यातायात दुर्घटनाओं को कम करेंगी, जिससे ड्राइवरों और पैदल यात्रियों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
5. आपदा प्रबंधन: शिमला, एक पहाड़ी क्षेत्र में होने के कारण, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के लिए प्रवण है। चौड़ी सड़कें आपातकालीन प्रतिक्रिया समय में सुधार करेंगी, जिससे आपदा प्रबंधन और आपात स्थिति के दौरान निकासी में सहायता मिलेगी।
6. पर्यावरणीय लाभ: जबकि सड़क चौड़ीकरण में भूमि अधिग्रहण शामिल है, यातायात के बेहतर प्रवाह और कम भीड़भाड़ से वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में भी कमी आएगी, जिससे समय के साथ पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

ये सार्वजनिक उद्देश्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि एमडीआर 66 और एमडीआर 67 को चौड़ा करने के लिए भूमि अधिग्रहण स्थानीय आबादी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार और दीर्घकालिक क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने की दिशा में एक आवश्यक कदम है।

7.2 कम विस्थापन विकल्प और न्यूनतम भूमि आवश्यकता

वर्तमान प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण का उद्देश्य मौजूदा सड़कों एमडीआर 66 और एमडीआर 67 को चौड़ा करना है। चूंकि चौड़ीकरण के लिए मौजूदा सड़क से सटी हुई भूमि की आवश्यकता होती है, इसलिए इस उद्देश्य के लिए अलग-अलग भूमि क्षेत्रों का चयन करने के अलावा कोई व्यवहार्य विकल्प नहीं है। अधिग्रहण के लिए पहचानी गई वर्तमान भूमि विस्थापन को कम करने और तकनीकी और नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए सड़क विस्तार को सुविधाजनक बनाने के लिए न्यूनतम आवश्यक है। परियोजना की प्रकृति को देखते हुए, कहीं और भूमि अधिग्रहण करने का कोई व्यवहार्य विकल्प नहीं है, क्योंकि चौड़ीकरण सीधे मौजूदा सड़क संरक्षण के निकटवर्ती भूमि का उपयोग करने पर निर्भर करता है।

7.3 सामाजिक प्रभावों की प्रकृति और तीव्रता

यदि कोई प्रभाव स्थायी प्रकृति का है, तो निर्माण के बाद के चरण के दौरान उसकी तीव्रता उतनी ही होगी जितनी निर्माण-पूर्व/निर्माण चरण के दौरान थी, दूसरी ओर अस्थायी प्रभावों में परियोजना चक्र के बाद के चरणों के दौरान तीव्रता में निरंतर कमी दिखाई देगी। निर्माण चरण के बाद भी रहने वाला कोई भी प्रभाव दीर्घकालिक प्रभाव माना जाता है और यदि यह निर्माण चरण तक ही रहता है, तो इसे अल्पकालिक प्रभाव माना जाता है। नीचे दी गई तालिका परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों के दौरान पहचाने गए विभिन्न प्रभावों की प्रकृति और तीव्रता को दर्शाती है।

7.4 सुझाए गए शमन उपायों की व्यवहार्यता

अध्ययन द्वारा सुझाए गए शमन उपायों पर सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एस० आई० एम० पी०) के अंतर्गत विस्तार से चर्चा की गई है। प्रभावित परिवारों की राय और मांगों के आधार पर, परियोजना के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हैं।

तालिका 7-1 प्रभावों की प्रकृति और तीव्रता

प्रभाव क्षेत्र	क्र. सं.	पहचाना गया प्रभाव	परियोजना चक्र का चरण	प्रभाव की प्रकृति	प्रभाव की तीव्रता
सामाजिक	1.	मुआवजा प्राप्त करने के लिए हितधारकों के बीच विवाद	पूर्व निर्माण	अस्थायी	अल्पावधि
भूमि/ संरचना	2.	भूमि की हानि	निर्माण चरण	स्थायी	दीर्घावधि
	3.	PAPs के लिए आश्रय का नुकसान		स्थायी	दीर्घावधि
	4.	भूमि और संपत्ति के अधिग्रहण पर सीधे निर्भर लोगों के लिए आजीविका के विकल्प का नुकसान। उदाहरण के लिए: दुकानदार, छोटे व्यवसाय		स्थायी	दीर्घावधि
	5.	निर्माण गतिविधि और उत्खनन के कारण वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है।	निर्माण चरण	अस्थायी	दीर्घावधि
* स्रोत: टीम एसआईए					

स्थानीय आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, विशेष रूप से भूमि और संपत्ति के मालिक, एमडीआर 66 और एमडीआर 67 के चौड़ीकरण के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के पक्ष में नहीं हैं। संपत्ति मालिकों द्वारा उठाई गई प्राथमिक चिंताओं में से एक मौजूदा कानूनी ढांचे के तहत दिए जाने वाले मुआवजे की अपर्याप्तता है। उनका मानना है कि सर्किल दरों पर आधारित मुआवजा उनकी भूमि और संपत्तियों के मौजूदा बाजार मूल्य से बहुत कम है, जिससे उन्हें वित्तीय घाटा हो रहा है। कई लोगों के लिए, उनकी संपत्तियां दीर्घकालिक निवेश का प्रतिनिधित्व करती हैं, और उन्हें चिंता है कि बाजार मूल्य और सर्किल दरों के बीच असमानता को देखते हुए, नकद मुआवजा कहीं और तुलनीय संपत्ति हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

भूमि मालिकों के अलावा, इन संपत्तियों पर कब्जा करने वाले किरायेदारों ने भी महत्वपूर्ण चिंताएँ व्यक्त की हैं। कई किराएदारों को डर है कि, हालांकि वे कानूनी मालिक नहीं हैं, लेकिन वे अपने अधिकारों और उन संपत्तियों तक पहुंच खो देंगे जिन्हें वे वर्षों से किराए पर दे रहे हैं। इन संपत्तियों के अधिग्रहण के साथ, किराएदारों को चिंता है कि वे किसी भी तरह के मुआवजे के

हकदार नहीं होंगे, क्योंकि मौजूदा कानूनी तंत्र मुख्य रूप से संपत्ति मालिकों को पूरा करते हैं। इसके अलावा, उन्हें नए वाणिज्यिक या आवासीय स्थानों पर स्थानांतरित होने की चुनौती का सामना करना पड़ता है, अक्सर वर्तमान में भुगतान की जाने वाली दरों से बहुत अधिक किराया देना पड़ता है। आस-पास के इलाकों में बढ़ती संपत्ति और किराए की कीमतों के कारण यह बहुत कम संभावना है कि उन्हें सस्ती दरों पर समान स्थान मिलेंगे, जो संभावित रूप से उनकी आजीविका और व्यवसायों को बाधित कर सकता है।

संपत्ति मालिकों और किराएदारों दोनों के बीच ये व्यापक चिंताएँ प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के बारे में बढ़ते असंतोष को उजागर करती हैं। अपर्याप्त मुआवजे का डर और किराएदारों का सस्ती जगहों से संभावित विस्थापन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के हिस्से के रूप में संबोधित करने की आवश्यकता है। पुनर्वास योजनाओं को आरटीएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 और एचपी आरटीएफसीटीएलएआरआर नियम 2015 और नवीनतम R&R नीति के अनुसार डिज़ाइन किया जाना चाहिए।

परियोजना प्राधिकारियों को भूमि अधिग्रहण की लागत (मुआवजा और आय बहाली उपायों सहित) को सहमत कार्यान्वयन अवधि के भीतर कवर करने के लिए पर्याप्त बजटीय सहायता पूरी तरह से प्रतिबद्ध और उपलब्ध करानी चाहिए। पुनर्वास के लिए आवश्यक मुआवजे और अन्य स्वीकार्य सहायता का प्रावधान करने से पहले विस्थापन नहीं होगा।

परिसंपत्तियों का अधिग्रहण, मुआवजे का भुगतान, और परियोजना प्रभावित परिवारों के आजीविका पुनर्वास गतिविधियों की शुरुआत और पुनर्वास परियोजना निर्माण गतिविधियों से पहले पूरा किया जाना चाहिए। आजीविका और आय बहाली के उपाय भी लागू होने चाहिए।

यह कहने के बाद कि यदि अपेक्षित निकाय और राज्य सरकार परियोजना प्रभावित परिवारों और समुदाय के विभिन्न नुकसानों को कम करने के लिए उचित उपाय करती है और राज्य के सकारात्मक विकास और हितों पर विचार करती है, तो परियोजना के लाभ परियोजना की प्रतिकूल सामाजिक लागत को काफी हद तक कम कर देंगे।

7.4.1. अंतिम अनुशंसा

अधिकांश परियोजना-प्रभावित व्यक्ति (पीएपी) एमडीआर 66 और एमडीआर 67 सड़कों के चौड़ीकरण के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि इससे उनकी भूमि,

संपत्ति और स्थापित व्यवसायों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। इनमें से कई व्यक्तियों और परिवारों के पास पीढ़ियों से भूमि और संपत्ति का स्वामित्व है, और वे अपने पैतृक घरों, आजीविका और स्थापित व्यवसायों को खोने के बारे में सोच रहे हैं।

संपत्ति मालिकों के लिए, भूमि का नुकसान केवल एक वित्तीय चिंता नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक और सांस्कृतिक चिंता है। कई लोगों ने अपनी संपत्तियों को विकसित करने या व्यवसाय स्थापित करने में महत्वपूर्ण संसाधनों का निवेश किया है, और उन्हें डर है कि मुआवजा मिलने के बाद भी, स्थानांतरण उनके जीवन को स्थायी रूप से बाधित कर देगा। स्थापित व्यवसाय जिन्होंने वर्षों में स्थानीय ग्राहक आधार बनाया है, वे विशेष रूप से असुरक्षित हैं, क्योंकि स्थानांतरण से ग्राहक खो सकते हैं और परिचालन लागत बढ़ सकती है, जिसकी पर्याप्त भरपाई नहीं हो सकती है।

जबकि सरकार इन चिंताओं से अवगत है और वित्तीय मुआवजे और वैकल्पिक आवास या व्यावसायिक स्थानों सहित पीएपी को उचित पुनर्वास और पुनर्वास पैकेज प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, इन उपायों को अक्सर प्रभावित पक्षों द्वारा अपर्याप्त माना जाता है। पीएपी के बीच एक आम धारणा है कि प्रदान किया गया मुआवजा उनकी संपत्तियों के वास्तविक बाजार मूल्य को प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है या उनके जीवन और आजीविका में दीर्घकालिक व्यवधान के लिए पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता है। किरायेदारों, विशेष रूप से, चिंतित हैं कि रहने वालों के रूप में उनके अधिकारों की रक्षा नहीं की जाएगी, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार के मुआवजे या किफायती विकल्पों के बिना विस्थापित होना पड़ेगा।

हालाँकि, इन चिंताओं के बावजूद, सरकार का दृष्टिकोण यह है कि यह परियोजना शिमला शहर और उसके निवासियों के व्यापक कल्याण के लिए आवश्यक है। शहर के तेजी से विकास और यातायात की बढ़ती मात्रा ने एमडीआर 66 और एमडीआर 67 पर गंभीर भीड़भाड़ पैदा कर दी है, जो शहर के लिए महत्वपूर्ण सड़कें हैं। वर्तमान सड़क की स्थिति बढ़ते वाहनों के यातायात को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिससे अक्सर अड़चनें, देरी और कुछ मामलों में दुर्घटनाएँ भी होती हैं।

सरकार के दृष्टिकोण से, इन प्रमुख जिला सड़कों के माध्यम से यातायात का सुचारु प्रवाह शहर के विकास और इसके निवासियों की समग्र भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। चूंकि शिमला एक

प्रमुख आर्थिक, प्रशासनिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विस्तार करना जारी रखता है, इसलिए इन मांगों को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे को उन्नत किया जाना चाहिए। एमडीआर 66 और एमडीआर 67 को चौड़ा करना यातायात की भीड़ को कम करने, सुरक्षा में सुधार करने और शहर के निवासियों और आगंतुकों के लिए पहुंच बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है।

इसके अलावा, सरकार का इरादा न केवल यातायात की स्थिति में सुधार करना है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि परियोजना से विस्थापित लोगों को उचित मुआवजा, पर्याप्त पुनर्वास और पुनर्वास के अवसर प्रदान किए जाएं। चुनौती व्यापक सार्वजनिक हित को संतुलित करने में है, जिसमें शिमला शहर के सभी निवासियों की भलाई और बेहतर बुनियादी ढांचे के दीर्घकालिक लाभ शामिल हैं, जो अधिग्रहण से सीधे प्रभावित लोगों के व्यक्तिगत हितों के साथ हैं।

निष्कर्ष में, जबकि पीएपी की चिंताएँ वैध हैं और उन्हें सहानुभूति और निष्पक्षता के साथ संबोधित करने की आवश्यकता है, परियोजना शिमला के भविष्य के विकास और कार्यक्षमता के लिए आवश्यक है। यह एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचागत सुधार है जिसका उद्देश्य शहर के दीर्घकालिक विकास को सुनिश्चित करना है, साथ ही यातायात की भीड़ को कम करके और सड़क सुरक्षा में सुधार करके इसके निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।

8. सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना

सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एस० आई० एम० पी०) एक रणनीतिक ढांचा है जिसे शिमला, हिमाचल प्रदेश में एमडीआर -66 और एमडीआर -67 के विस्तार से उत्पन्न होने वाले प्रतिकूल सामाजिक प्रभावों को कम करने, प्रबंधित करने और निगरानी करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परियोजना सभी हितधारकों के लिए समान परिणामों को बढ़ावा देते हुए प्रभावित समुदायों के लिए व्यवधानों को कम से कम करे। एस० आई० एम० पी० में भूमि अधिग्रहण और निर्माण गतिविधियों से प्रभावित व्यक्तियों और समूहों की सामाजिक-आर्थिक भलाई को संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए मुआवज़ा उपायों, पुनर्वास सहायता, हितधारक जुड़ाव और शिकायत निवारण तंत्र सहित प्रमुख हस्तक्षेपों की रूपरेखा दी गई है। स्थानीय समुदायों के साथ सावधानीपूर्वक योजना और सहयोग के माध्यम से, योजना का उद्देश्य कानूनी ढाँचों और परियोजना लक्ष्यों के साथ संरेखण में सतत विकास को बढ़ावा देना, कमजोर आबादी की रक्षा करना और सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाना है।

8.1 शमन का दृष्टिकोण

यह सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एसआईएमपी) आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 और हिमाचल प्रदेश आरटीएफसीटीएलएआरआर नियम, 2015 के अनुसार तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य छोटा शिमला-कसुम्पटी लिंक रोड पर तिब्बती स्कूल के पास पैदल पथ सहित एमडीआर 66 और एमडीआर 67 के चौड़ीकरण के नकारात्मक सामाजिक प्रभावों को कम करना और सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाना है। एसआईएमपी को परियोजना के विभिन्न चरणों अर्थात् निर्माण-पूर्व चरण, निर्माण चरण और परिचालन चरण के दौरान क्रियान्वित किया जा सकता है। परियोजना के विभिन्न चरणों के दौरान सुझाए गए विभिन्न प्रबंधन उपायों का विवरण निम्नलिखित अनुभाग में दिया गया है।

8.2 प्रभावों से बचने, उन्हें कम करने और क्षतिपूर्ति करने के उपाय

1. यदि हितधारकों के बीच कोई विवाद है, तो पहले इस विवाद को सुलझाया जाना चाहिए और सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मुआवजा कानूनी मालिक को दिया जाए।
2. परियोजना प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों ने बाजार मूल्य से मुआवजे की गणना करने से पहले सर्किल दरों को अद्यतन करने और बढ़ाने का अनुरोध किया है।
3. सरकार को परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) के व्यवसायों के पुनर्वास के लिए दुकानों या समर्पित वाणिज्यिक परिसर जैसी जगह आवंटित करनी चाहिए।
4. चर्चा के दौरान, कई लोगों ने तिब्बती बाजार के सफल पुनर्वास का उदाहरण दिया, जहाँ विस्थापित विक्रेताओं की सहायता के लिए आजीविका भवन नामक एक वाणिज्यिक परिसर का निर्माण किया गया था। यह दृष्टिकोण प्रभावित व्यवसाय मालिकों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि पुनर्वास के बाद उनकी आजीविका बनी रहे।
5. निष्पादन चरण के दौरान पर्यावरण और पारिस्थितिकी क्षरण का जोखिम है यदि तूफानी पानी के सुरक्षित मार्ग के लिए उचित उपाय नहीं किए जाते हैं और निष्पादन चरण के दौरान उत्पन्न होने वाले मलबे से प्राकृतिक धाराओं के प्राकृतिक जल निकासी में किसी भी तरह की बाधा को रोकने के लिए उचित उपाय नहीं किए जाते हैं।

8.3 अधिनियम 2013 के अनुसार पुनर्वास और पुनर्वास में शामिल उपाय और मुआवजा

यह एस०आई०ए रिपोर्ट भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करने और सार्वजनिक परामर्श और सर्वेक्षण के दौरान परियोजना प्रभावित परिवारों और अन्य हितधारकों द्वारा व्यक्त की गई आकांक्षा के अनुसार कार्य योजना तैयार करने के लिए आवश्यक निकाय के लिए फायदेमंद होगी। अध्ययन के निष्कर्षों के आलोक में, अपेक्षित सामाजिक प्रभावों को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:

तालिका 8-1 पहचाने गए प्रभाव और तदनुरूप शमन उपाय

क्र. सं.	मूल्यांकित प्रभाव	सुझाए गए शमन उपाय
1	निजी भूमि की हानि	आरटीएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार शीर्षक धारकों और हितधारकों को उचित मुआवजा
2	अधिग्रहण के कारण आवासीय और वाणिज्यिक संरचनाओं जैसी निजी परिसंपत्तियों की हानि।	आरटीएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार मालिकों और हितधारकों को उचित मुआवजा
	सर्किल दरों में संशोधन	जिला कलेक्टर एवं अधिसूचित निकाय के निर्णय के अनुसार
3	अधिग्रहण के कारण विस्थापित परिवारों और व्यक्तियों को होने वाली असुविधा	नए स्थान पर स्थानांतरित होने और नए घरों के निर्माण के लिए आरटीएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार मालिकों और हितधारकों को उचित मुआवजा
4	भूमि पर निर्भर रोजगार/आय/आजीविका का नुकसान।	आरटीएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार व्यक्तियों को उचित मुआवजा।

8.3.1. एसआईएमपी कार्यान्वयन के लिए परिव्यय

परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए लागू कानूनी प्रावधानों की पृष्ठभूमि में पात्रता रूपरेखा और पुनर्वास और पुनर्स्थापन की प्रक्रिया नीचे प्रस्तुत की गई है।

भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों, नियमों और नीतियों के अनुपालन में एक पात्रता मैट्रिक्स विकसित किया गया है। पात्रता मैट्रिक्स में नुकसान के प्रकार और पात्रता की संगत प्रकृति और दायरे का सारांश दिया गया है।

तालिका 8-2 पात्रता मैट्रिक्स

क्र. सं.	प्रभाव श्रेणी	पात्रता की इकाई	पात्रता का विवरण	टिप्पणियाँ
परिसंपत्तियों की हानि- शीर्षकधारक				
1	निजी भूमि	भूमि मालिक/शीर्षकधारक	<p>(क) भूमि के लिए बाजार मूल्य पर नकद मुआवजा, जो आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।</p> <p>(ख) खोई हुई संपत्तियों के प्रतिस्थापन के लिए मुआवजा राशि पर वर्तमान स्टॉप शुल्क के बराबर राशि।</p> <p>प्रशिक्षण सहायता</p> <p>ग) बारहमासी और गैर-बारहमासी फसलों और पेड़ों के नुकसान की भरपाई बागवानी और कृषि विभाग के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।</p> <p>घ) मवेशी शेड या छोटी दुकानों के प्रतिस्थापन के लिए 25,000 रुपये का अनुदान।</p>	
2	संरचना का नुकसान (आवासीय या वाणिज्यिक या पुनर्वास-सह-वाणिज्यिक)	भूमि मालिक/शीर्षकधारक	<p>क) स्वीकार्य मानदंडों के अनुसार वर्तमान दरों के आधार पर निर्धारित नकद मुआवजा</p> <p>(ख) विस्थापित परिवारों के लिए आर.एफ.सी.टी.एल.ए.आर.आर. अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार 50,000 रुपये का स्थानांतरण भत्ता</p> <p>(ग) पूर्ण रूप से विस्थापित आवासीय/वाणिज्यिक के लिए आर.एफ.सी.टी.एल.ए.आर.</p>	

			<p>अधिनियम, 2013 के अनुसार निःशुल्क आवास का प्रावधान अथवा निर्मित आवास के बदले में आवास की समतुल्य लागत की पेशकश की जा सकती है</p> <p>(घ) विस्थापित परिवारों के लिए 36,000 रुपये का निर्वाह भत्ता (आर.एफ.सी.टी.एल.ए.आर. अधिनियम, 2013)</p> <p>(ड) विस्थापित परिवारों के लिए 50,000 रुपये का पुनर्वास भत्ता (आर.एफ.सी.टी.एल.ए.आर. अधिनियम, 2013)</p>	
3	किरायेदार और पट्टाधारक	किरायेदार और पट्टाधारक	पंजीकृत पट्टेदार, लागू स्थानीय कानूनों के अनुसार संरचना स्वामी को देय मुआवजे के विभाजन के हकदार होंगे।	
आवासीय और व्यावसायिक संरचनाओं का नुकसान - गैर-शीर्षकधारक				
4	कब्ज़ाधारक	प्रभावित व्यक्ति (व्यक्तिगत/परिवार)	<p>(क) अतिक्रमणकारियों को संपत्ति/फसल हटाने के लिए 2 महीने का अग्रिम नोटिस दिया जाएगा।</p> <p>(ख) प्रभावित संरचना से सामग्री को बचाने का अधिकार</p>	
आजीविका का नुकसान - शीर्षक और गैर-शीर्षकधारक				

5	आजीविका का नुकसान – शीर्षक धारक, और वाणिज्यिक अवैध कब्जाधारी	(व्यक्तिगत/ परिवार)	25,000 रुपये का एकमुश्त अनुदान (आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित मूल्य)	वाणिज्यिक अवैध निवासियों के लिए पात्रता जनगणना सर्वेक्षण की तिथि से होगी
6	निर्माण चरण के दौरान संभावित और अप्रत्याशित प्रभाव	मालिक, प्रभावित व्यक्ति	यदि कोई क्षति हुई है तो उसका भुगतान संरचनाओं को अस्थायी पहुंच प्रदान की जाएगी, जहां भी आवश्यक हो	जैसे कि संरचनाओं पर अस्थायी प्रभाव, पहुँच या मार्ग में अस्थायी व्यवधान
7	मोबाइल कियोस्क की आय में अस्थायी हानि, यदि कोई हो	कियोस्क मालिक	क्षेत्र खाली करने के लिए दो महीने पहले नोटिस	
8	एससी, एसटी		सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में शामिल करने के लिए सहायता, यदि सरकारी मानदंडों के अनुसार पात्र नहीं है; और आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 द्वितीय अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार एससी और एसटी को अतिरिक्त लाभ	
9	अप्रत्याशित प्रभाव		किसी भी अप्रत्याशित प्रभाव को अधिनियम के सिद्धांतों और उद्देश्यों के अनुसार दस्तावेजित और कम किया जाएगा।	

